वर्ष-10, अंक-11, अगस्त-2025

मूल्यः ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

TRADE WAR

अमेरिकी दादागिरी पर मोदी की ललकार

मिशन रोज़गार

8.5 लाख+	3.75 लाख+	2 करोड़+
सरकारी नौकरी	संविदा पर नौकरी	निजी क्षेत्र/ एमएसएमई में रोजगार

उत्तर प्रदेश में
आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती में महिला शक्ति

12,048 महिला अभ्यर्थियों का चयन

27,178	10,378	78	1,596
महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति	महिला बीटों का आवंटन	महिला पुलिस परामर्श केन्द्र	महिला हेल्प डेस्क की स्थापना

- प्रत्येक जनपद में महिला थाने के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष की तैनाती
- लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी बटालियन का गठन

काम दमदार डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

अन्दर के पेजों में...

वर्ष- 10 अंक- 11

अगस्त-2025

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

डेमोग्राफी मिशन से राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगा नया आधार — पेज 03

जांबाज आईपीएस डॉ. प्रवीण रंजन सिंह को मिली नोएडा पुलिस उपायुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी — पेज 05

राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोप से गरमाई बहस, चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल — पेज 10

योगी सरकार के प्रयासों से देश-विदेश में खुल रहे रोजगार के अवसर — पेज 16

...फिर चल पड़ी काजोल के कैरियर की गाड़ी — पेज 52

खेल-इंडिया क्रिकेट खेलने की विवशता — पेज 55

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

अमेरिकी दबाव के खिलाफ भारत की नई कूटनीतिक मोर्चेबंदी

ललित कुमार
सम्पादक

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार ऐसे समीकरण भी देखे जाते हैं, जिन्हें परिस्थितियों की उपज माना जाता है, लेकिन कई बार कुछ ताकतवर देशों की नाहक जिद की वजह से भी नए हालात बनते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जरूरत की वस्तुओं का आयात-निर्यात न केवल आर्थिक मोर्चे पर परस्पर सहयोग का मजबूत आधार रहे हैं, बल्कि यह सामान्य संबंधों में भी सहजता के वाहक रहे। मगर इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आंतरिक मोर्चे पर कई विवादित फैसले लेने के साथ-साथ अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाने की नीति अपना कर उन पर जैसी मनमानी नीतियां थोपने और उन्हें अपने मुताबिक संचालित करने की कोशिश की है, उससे नई समस्या पैदा हुई है।

खासतौर पर भारत को निशाना बना कर अमेरिका ने जो एकतरफा तौर पर बेलगाम शुल्क थोपने की घोषणा की, उससे भारत के सामने नई परिस्थितियों से निपटने की चुनौती खड़ी हुई है। यह स्थिति तब है, जब हाल के वर्षों में भारत ने अमेरिका के साथ हर स्तर पर सहयोगात्मक रुख ही अपनाया।

सवाल है कि अगर अमेरिका बेलगाम शुल्क लगाने की नीति के जरिए भारत के सामने जटिल स्थितियां पैदा करने की कोशिश जानबूझ कर नहीं कर रहा है तो इसके क्या कारण हैं कि वह वस्तुस्थिति और औचित्य की अनदेखी करके भारत पर दबाव बनाना चाहता है। यही नहीं, उसने रूस से तेल खरीदने के सवाल पर भारत पर जुमार्ना लगाने तक की घोषणा की।

मौजूदा दौर में बहुध्रुवीय होते विश्व में अगर भारत या कोई भी अन्य देश अपनी जरूरत के मुताबिक आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका की सुविधा से इतर कोई उपाय अपनाता है तो वह कैसे गलत हो सकता है। दिलचस्प है कि अमेरिका ने भारत पर शुक्ल थोपने को लेकर जिस तरह का रवैया अपनाया है, उसे सही ठहराने के लिए खुद उसके पास भी उचित तर्क नहीं हैं।

यही वजह है कि उसके पास फिलहाल सिर्फ दबाव बनाने की भाषा है और उसी के तहत वह भारत को संचालित करने की मंशा रखता है। एक संप्रभु और लोकतांत्रिक देश होने के नाते स्वाभाविक ही भारत ने दबाव के आगे कमजोर पड़ने के बजाय इसका विकल्प निकालने की कोशिश शुरू कर दी है।

दरअसल, नई चुनौतियों से निपटने की कोशिश के तहत ही भारत ने रूस और चीन के साथ उच्चस्तरीय वार्ता की राह अपनाई है। इस क्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोह के साथ महत्त्वपूर्ण बातचीत के लिए मास्को जाएंगे, तो दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत की यात्रा पर आएंगे।

संभावना यह भी जताई जा रही है कि इस वर्ष के अंत में रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की भारत यात्रा के विभिन्न पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके अलावा, ह्यब्रिक्सह्ल की नीतियों को पहले ही एक मजबूत मोचेर्बंदी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। अब एक बार फिर उसके मुखर होने की उम्मीद जताई जा रही है। जाहिर है, भारत पर दबाव के बरक्स नए समीकरणों की संभावना अमेरिका के लिए शायद चिंता की बात होगी। मगर भारत को यह ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान चीन का भारत के प्रति जो रवैया रहा है, उस पर वह आगे क्या रुख अपनाता है। फिलहाल अमेरिकी दबाव की नीति के बरक्स अपने हित और सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए नई कूटनीतिक मोचेर्बंदी भारत के लिए वक्त की जरूरत है।

सवाल है कि अगर अमेरिका बेलगाम शुल्क लगाने की नीति के जरिए भारत के सामने जटिल स्थितियां पैदा करने की कोशिश जानबूझ कर नहीं कर रहा है तो इसके क्या कारण हैं कि वह वस्तुस्थिति और औचित्य की अनदेखी करके भारत पर दबाव बनाना चाहता है। यही नहीं, उसने रूस से तेल खरीदने के सवाल पर भारत पर जुमार्ना लगाने तक की घोषणा की।

डेमोग्राफी मिशन से राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगा नया आधार

संजीव कुमार

दुनिया के देशों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाती है। चीन जैसे देश तो इतने कठोर कदम उठाते हैं कि कभी पता ही नहीं चल सकता की स्वतंत्रता क्या होती है उसका पता ही नहीं चलता। अफगान सीमा पर तो गोली मार दी जाती है।

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए हाईपॉवर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा कर देश के सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठियों और अन्य कारणों से देश में आ रहे डेमोग्राफी बदलाव की समस्या के समाधान की आस बंधी है। देश के कुछ हिस्सों खासतौर से सीमावर्ती जिलों में आबादी असंतुलन से बड़ी समस्या होती जा रही है। डेमोग्राफी मिशन को राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। अपितु जो तस्वीर देश में सामने आ रही है उससे सबसे बड़ी और गंभीर समस्या सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर आ गई है। हांलाकि राजनीतिक दल वोट बैंक के चलते बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं सहित अवैध प्रवास कर रहे लोगों के पक्ष में आ जाते हैं पर यह सीधा-सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। पिछले दिनों अमेरिका के लॉस एंजिल्स की घटना पर ध्यान दिया जाना जरुरी हैं जहां वाहनों को जलाते और लूटपाट मचाकर कानून व्यवस्था को ही तहस-नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फ्रांस में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। रवांडा, पश्चिमी वाल्मिक, यारोपीय देश आदि दुनिया के अनेक देश इस समस्या से दो चार होते रहे हैं। अमेरिका के चुनाव परिणाम किस तरह से लांस एंजिल्स में प्रभावित होते हैं वह सबके सामने हैं। हमारे देश में पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, झारखण्ड आदि कई दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या अवैध घुसपैठ कर देश के हर कोने में आसानी से पहुंच रहे हैं और जब किसी तरह की घटना होती हैं तो इनके द्वारा आंतक और अशांति फैलाई जाती है वह भी किसी से नहीं है।

दुनिया के देशों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ

सख्ती से कार्रवाई की जाती है। चीन जैसे देश तो इतने कठोर कदम उठाते हैं कि कभी पता ही नहीं चल सकता की स्वतंत्रता क्या होती है उसका पता ही नहीं चलता। अफगान सीमा पर तो गोली मार दी जाती है। क्यूबा में राजनीतिक जेल में बंद हो जाते हैं। सउदी अरब में भी जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक इसके विपरीत हमारे हालात है। हमारे यहां राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। सोशल एक्टिविस्ट सक्रिय हो जाते हैं। हमारे यहां तो अवैध कब्जा, राशनकार्ड, निःशुल्क सुविधाओं से लाभान्वित करवाने वाले सक्रिय हो जाते हैं। सच में देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा से एक तरह से लेना देना ही नहीं रहता। यही कारण है कि बांग्लादेशी हो या रोंहिग्या हो या पाकिस्तान परस्त लोग देश की सुरक्षा और अशांति फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। ज्योंही कहीं पर कोई कार्रवाई करने को प्रशासन आगे आता है तो इनके बचाव में मानवीयता का नारा उछालने लगते हैं। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण हालात है।

डेमोग्राफी का सबसे पहले प्रयोग 1855 में बेल्जियम के अकिल गुडलार्ड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेमोग्राफी में किया। हांलाकि जनसांख्यकी की बात राबर्ट माल्थस 1766 से 1834 में कर चुके हैं और उन्होंने पूरी थ्योरी प्रस्तुत की है। डेमोग्राफिक अध्ययन को दो तरह से समझना पड़ेगा। एक तो सामान्य तौर पर जिस तरह से आयु-धर्म के आधार पर जनसांख्ययीय अध्ययन कर विकास की रुपरेखा तैयार की जाती है। यह एक तरह से इस समस्या का समाधान डेमोग्राफिक अध्ययन के परिणामों के आधार पर नीति व योजनाएं बनाकर की जाती है और की जा सकती है। इसके ठीक विपरीत जिस तरह से देश में अराजकता और अशांति फैलाने और घुसपैठ व वर्गविशेष के कारण जनसंख्या में बदलाव लाकर क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करने का प्रयास किया जाता है वह अधिक गंभीर व चिंतनीय हो जाती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डेमोग्राफी मिशन की घोषणा के निश्चित रुप से राजनीतिक अर्थ निकालने के प्रयास किये जायेंगे। इसे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक द्वारा घुसपैट और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध मदरसों आदि द्वारा संचालित गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है उससे जोड़कर देखने का प्रयास किया जाएगा। यहां इसको भी ध्यान में रखना होगा कि अवैध घुसपैठियों द्वारा सीमावर्ती जिलों में जिस तरह से आदिवासियों की जमीन और संपत्ती पर कब्जा किया जा रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं हैं। बीएसएफ और एसएसएफ द्वारा जिस तरह से सरकार को लगातार रिपोर्टें दी जाती रही हैं पहलीवार उसे गंभीरता से लिया जा रहा है। बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा का कहना है कि डेमोग्राफी मिशन को राजनीतिक चश्में से नहीं देखा जाना चाहिए। यह तो सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। आज समूचा देश डेमोग्राफिक समस्या से दो चार हो रहा है। इसे नेपाल, बांग्लादेश, सीमावर्ती इलाकों में मुसलमान और हिंदुओं की आबादी में आ रहे बदलाव आदि से देखना होगा। प्रधानमंत्री की चिंता किसी एक क्षेत्र या सीमा तक नहीं है। इसका बड़ा कारण देश में डेमोग्राफिक समस्या की गंभीरता को समझने से ही होगा। आने वाले दिनों में बिहार, बंगाल आदि में चुनाव होने हैं और राजनीतिक दल इस घोषणा को निश्चित रुप से मुद्दा बनायेंगे, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। पर धरातलीय समस्या से आंख नहीं मूंदी जा सकती। बंगाल की मुर्शिदाबाद, बिहार का किशनगंज, उत्तरप्रदेश का नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, असम के आदिवासी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल और झारखण्ड के हालात सामने हैं। सीमावर्ती सहित इन क्षेत्रों में मदरसों द्वारा जिस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है उससे डेमोग्राफी बदलती जा रही है। कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है आज कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से विस्थापन हो चुका है।

डेमोग्राफी मिशन के पक्ष विपक्ष में अंतहिन विवाद किया जा सकता है पर दो टके का सवाल यही है कि देश को किसी भी हालत में आंतरिक व राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिये। जिस तरह से देश के कई पॉकेट्स में तेजी से डेमोग्राफिक असंतुलन बन रहा है उसे देखते हुए देरी से ही सही पर डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा स्वागतीय है। सभी को दलीय राजनीति से उपर उठकर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह साफ हो जाना चाहिए कि देश की आंतरिक और सीमावर्ती सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र इसे स्वीकार भी नहीं करेगा। घुसपैठियों के कारण जिस तरह की समस्याएं और आदिवासियों की भूमि पर कब्जा करने से लेकर देश की आम जनता के लिए लोक हितकारी योजनाओं में सैंध लगा रहे हैं उसे रोका जाना अतिआवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस भावना के साथ मिशन की घोषणा की है उसी भावना और मंशा के साथ इस मिशन को आकार दिया जाना चाहिए और पूरी कार्ययोजना बनाकर इसे जल्द से जल्द से आकार दिया जाना चाहिए ताकि डेमोग्राफिक मिशन अपना कार्य आरंभ कर सके। डेमोग्राफिक संतुलन व सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही योजनावद्ध तरीके से असंतुलन के जो प्रयास किये जा रहे हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना जरुरी है। इसे राजनीतिक विवाद से दूर ही रखा जाना चाहिए। सोशल एक्टिविस्टों को भी राष्ट्रहित को पहली प्राथमिकता देनी ही होगी।

जांबाज आईपीएस डॉ. प्रवीण रंजन सिंह को मिली नोएडा पुलिस उपायुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

ललित कुमार

उत्तर प्रदेश पुलिस के जांबाज, निष्ठावान व कर्मठ आला पुलिस अधिकारियों में शुमार आईपीएस डॉ. प्रवीण रंजन सिंह को योगी सरकार ने नोएडा कमिश्नरेट में नोएडा पुलिस उपायुक्त जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

माना जा रहा है कि नोएडा जैसे महत्वपूर्ण जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रित करने व कानून व्यवस्था दुरुस्त करने करने के लिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुडबुक में शामिल आईपीएस डॉ. प्रवीण रंजन सिंह को नोएडा डीसीपी बनाकर भेजा गया है।

डॉ. प्रवीण रंजन सिंह एक बेहद सुलझे हुए व्यवहारिक पुलिस अधिकारी हैं। वे राजनीति शास्त्र में परास्नातक है। इसके साथ ही उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। शिक्षाविद् होने के साथ ही वे लॉ ग्रेजुएट भी हैं, जिसके चलते उन्हें कानून की बाराकियों की भी गहरी समझ है। डॉ. प्रवीण रंजन सिंह एक अनुभवी, कुशल एवं सजग अधिकारी हैं। उन्होंने पुलिस सेवा में बतौर पी.पी.एस अधिकारी 1997 से हैं। पीपीएस अधिकारी के रूप में उन्होंने अपने परिश्रम, कर्तव्य परायणता, निष्ठा और कार्यकुशलता के बदौलत भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नत हुए।

डॉ. प्रवीण रंजन सिंह मूल रुप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर रहने वाले हैं। एक पुलिस अधिकारी के रुप में वे सदैव अपने मधुर स्वभाव, दृढ़ निर्णय क्षमता और जनहित में त्वरित कार्यवाही के लिए जाने जाते हैं। इनकी इन्ही खूबियों व योग्यताओं के मद्देनजर ही उन्हें गौतम बुद्ध नगर की कानून व्यवस्था को नई दिशा और मजबूती देने के लिए ही नोएडा के डीसीपी जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनाती की गयी है।

यदि डॉ. प्रवीण रंजन सिंह के अब तक करियर पर नजर डाली जाए तो उनमें वर्ष 2010 से लेकर अब तक वे तमाम महत्वपूर्ण पदों पर अपने सेवा दे चुके हैं। इस दौरान वे गाजियाबाद जनपद में बतौर सी.ओ. (क्षेत्राधिकारी) गाजियाबाद, बिजनौर में सीओ एवं एस.पी. सिटी, बुलंदशहर में एसपी सिटी के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं।

डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह को भारतीय पुलिस सेवा पद पर पदोन्नति कर वर्तमान में अपर पुलिस उपयुक्त सेंट्रल नोएडा और पुलिस उपायुक्त (हेड क्वार्टर) जिला गौतम बुद्ध नगर में नियुक्त किया। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में डॉक्टर प्रवीण रंजन की नियुक्ति पुलिस उपायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पर होना न केवल नोएडा के लिए गौरव की बात है। वेलकम इंडिया भी उनकी इस महत्वपूर्ण तैनाती के लिए अपनी शुभकामनाएं देती है।

शिक्षा-चिकित्सा को मुनाफाखोरी से बचाने का भागवत-आह्वान

भारत में स्वास्थ्य-शिक्षा को प्रारंभ से ही सामाजिक दायित्व मानने की परंपरा रही है। लेकिन दुर्भाग्य से आज स्कूल-कॉलेज और अस्पताल लाभ संचालित उपक्रमों में तब्दील हो गए हैं और सेवा की बजाय धन कमाने के अड्डे बन गये हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने इंदौर के एक किफायती कैंसर अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर जो बात कही, वह आज की सबसे बड़ी सामाजिक-आर्थिक और नैतिक आवश्यकता को उजागर करती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा और चिकित्सा जैसे बुनियादी क्षेत्रों को मुनाफाखोरी से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये सेवा के क्षेत्र हैं, व्यापार के नहीं। हाल के वर्षों में शिक्षा और चिकित्सा का जिस तेजी से बाजारीकरण एवं व्यावसायीकरण हुआ है,

राहुल अग्रवाल

सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र ने इसे धन कमाने का जरिया बनाया है, वह न केवल नये समाज निर्माण की चिन्ताओं बल्कि एक दूषित सोच को दशार्ता है। क्योंकि उसने आम आदमी को बदहाली के कगार पर पहुंचाया है। महंगी शिक्षा ने जहां अभिभावकों का बजट हिला दिया है, वहीं चिकित्सा के नाम पर मुनाफाखोरी ने लाखों परिवारों को गरीबी के दलदल में धकेलते हुए जरूरी चिकित्सा से वंचित किया है। इस मर्ज की रग पर हाथ रखते हुए भागवत द्वारा दी गई चेतावनी सत्ताधीशों की आंख खोलने वाली है।

भारत में स्वास्थ्य-शिक्षा को प्रारंभ से ही सामाजिक दायित्व मानने की परंपरा रही है। लेकिन दुर्भाग्य से आज स्कूल-कॉलेज और अस्पताल लाभ संचालित उपक्रमों में तब्दील हो गए हैं और सेवा की बजाय धन कमाने के अड्डे बन गये हैं। आज निजी क्षेत्र के साथ-साथ

सरकारों की मानसिकता भी धन-केन्द्रित होती जा रही है, जिससे आमजन को सस्ते एवं किफायती शिक्षा एवं चिकित्सा के साधन-सुविधाएं सुलभ नहीं हो रही है। मुनाफाखोरी की अंतहीन लिप्सा ने कथित गुणवत्ता वाले स्कूलों व अस्पतालों को आम आदमी की पहुंच से दूर किया है। इन जटिल होती स्थितियों के बीच भागवत का यह बयान केवल एक सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है-सरकार, नीति-निमार्ताओं और समाज के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों ही मानव जीवन के मूलभूत स्तंभ हैं। लेकिन आज इन दोनों क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती व्यावसायिक प्रवृत्तियां इन्हें सेवा के बजाय मुनाफे की मशीन बना रही हैं। निजी स्कूलों की भारी फीस, कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा और महंगे मेडिकल कॉलेजों की ट्यूशन-इन सबने शिक्षा को गरीब और मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर कर दिया है। इसी तरह, अस्पतालों और दवा कंपनियों का अत्यधिक मुनाफा-उन्मुख मॉडल स्वास्थ्य को एक महंगे उत्पाद में बदल रहा है।

निस्संदेह, मोहन भागवत की यह चिंता हमारे समय की विसंगतियों एवं विकृत आर्थिक सोच पर तीखा प्रहार करती है। आज आम भारतीय परिवारों पर स्वास्थ्य सेवाओं का भारी वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। विडंबना यह है कि इस खर्च का छोटा हिस्सा ही सरकारी खजाने से वहन किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य खर्च का महज 17 फीसदी है। वहीं करीब 82 फीसदी स्वास्थ्य खर्च लोगों को मुश्किल हालात में वहन करना पड़ता है। इन स्थितियों के चलते अस्पताल में भर्ती होने के बाद कई परिवार जीवन भर के लिये कर्ज में डूब जाते हैं। तो कई परिवार हमेशा के लिये गरीबी की दलदल में धंस जाते हैं। आज देश की बड़ी आबादी गैर संक्रामक रोगों, मसलन हृदय रोग, मधुमेह व उच्च रक्तचाप आदि से जूझ रही है। इनकी जांच, चिकित्सकीय परामर्श और उपचार के लिये मरीजों को एक बड़ी रकम चुकाने को मजबूर होना पड़ता है। जो कि बीमा योजनाओं के द्वारा बमुश्किल ही पूरी की जाती है। इन विडम्बनापूर्ण एवं चिन्ताजनक स्थितियों के बीच मोहन भागवत का यह संदेश न केवल आर्थिक सुधार का आह्वान है, बल्कि सामाजिक पुनर्जागरण का भी। शिक्षा और चिकित्सा को व्यापार से मुक्त करना सिर्फ भावनात्मक या नैतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्र की स्थिरता और समानता का प्रश्न है। जब गरीब को इलाज न मिले, और होनहार छात्र को शिक्षा से वंचित रहना पड़े, तब असमानता, असंतोष और सामाजिक अशांति बढ़ती है। ऐसे में प्रधानमंत्री

मुनाफाखोरी की अंतहीन लिप्सा ने कथित गुणवत्ता वाले स्कूलों व अस्पतालों को आम आदमी की पहुंच से दूर किया है। इन जटिल होती स्थितियों के बीच भागवत का यह बयान केवल एक सामान्य टिप्पणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है-सरकार, नीति-निमार्ताओं और समाज के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों ही मानव जीवन के मूलभूत स्तंभ हैं।

नरेन्द्र मोदी का नया भारत, विकसित भारत, विश्वासभरा भारत का नारा कोरा दिखावा ही प्रतीत होता है।

नये भारत में जब आम जनता से करो के रूप में भारी भरकम रकम वसूली जा रही है, जो उस रकम को जनकल्याण एवं जनसेवा में खर्च किया जाना चाहिए। आजादी के बाद से सरकार पर शिक्षा एवं चिकित्सा की ही जिम्मेदारी डाली गयी थी, जिसको सरकारों ने बड़ी चतुराई से धीरे-धीरे निःशुल्क की बजाय सशुल्क करने की कारगरी दिखाई है, जो जनता के विश्वास को आहत करने वाली है। इसलिये भागवत का यह बयान सरकार के लिए आंख खोलने वाला होना चाहिए। नीति-स्तर पर ऐसे कदम जरूरी हैं जिनसे-सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों को उच्च गुणवत्ता के साथ सशक्त एवं जनसुलभ किया जाए। निजी क्षेत्र में फीस और इलाज की दरों पर प्रभावी नियंत्रण हो। सेवा-भाव को बढ़ाने के लिए कर-छूट और प्रोत्साहन मिलें, जबकि मुनाफाखोरी पर कठोर दंड लागू हो। स्वास्थ्य और शिक्षा में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू किया जाए, इन दोनों क्षेत्रों से धन कमाने की प्रवृत्तियों को अपराध माना चाहिए। यह भी तय किया जाये कि इन दोनों क्षेत्रों में सेवा एवं मिशन भावना से आने वालों को ही मान्य किया जाये, धन कमाने वालों के लिये इन दोनों क्षेत्रों के दरवाजे बन्द हो।

शिक्षा और स्वास्थ्य में मुनाफाखोरी को रोकना केवल कानून से संभव नहीं, इसके लिए समाज में मूल्य-आधारित सोच का विकास भी आवश्यक है। सेवा-भाव, मानवीय संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण मूल्याधारित आर्थिक ढांचा-यही स्थायी समाधान हैं। मोहन भागवत की यह पहल यदि नीतिगत बदलावों में परिणत होती है, तो यह भारत को न केवल आर्थिक दृष्टि से, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी मजबूत बनाएगी। भागवत ने कॉर्पोरेट शैली के कथित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के जुमले के बजाय लोककल्याण के धार्मिक सिद्धांतों के अनुसरण की भी अपील की। वर्तमान में कॉर्पोरेट जगत ने सीएसआर फण्ड को स्वयं के बनाये ट्रस्टों में दिखाकर सरकार के सीएसआर प्रावधानों की धज्जियां उडा रखी है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच और दर्शन में शिक्षा और चिकित्सा हमेशा ह्लसेवा और संस्कारह्व के मूल्यों से जुड़ी रही है। संघ मानता है कि राष्ट्र निर्माण का असली आधार स्वस्थ और शिक्षित नागरिक हैं, और इन दोनों आवश्यकताओं को समाज के हर वर्ग तक सस्ती, सुलभ और समान रूप से पहुंचाना ही सच्ची देशभक्ति है। डॉक्टर को केवल इलाज का शुल्क लेने वाला पेशेवर नहीं, बल्कि रोगी की पीड़ा का साझेदार मानना और शिक्षक को केवल पाठ पढ़ाने वाला कर्मी नहीं, बल्कि जीवन-निमार्ता के रूप में देखना-यही संघ का दृष्टिकोण है। इसी सोच के तहत भागवत का यह आह्वान है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मुनाफाखोरी के पंजे से मुक्त कर, इन्हें सेवा के आदर्श पर स्थापित किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न हो और कोई भी रोगी आर्थिक बोझ के कारण इलाज से दूर न रहे। सरस्वती के मंदिर एवं सेवा के आश्रय-स्थल आज व्यापार के केंद्र बन गये हैं, ये मिशन नहीं, व्यवसाय बन गये हैं। पिछले दिनों इससे जुड़ा जनाक्रोश तब चरम पर नजर आया जब हैदराबाद के एक स्कूल में नर्सरी में दाखिले की सालाना फीस ढाई लाख रुपये बतायी गई। जिससे अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त हो गया। जिसके बाद महंगी होती शिक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई। निस्संदेह, बढ़ती फीस के ये आंकड़े शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण एवं बाजारीकरण को भी रेखांकित करते हैं। ऐसे में भागवत की हालिया अपील सत्ताधीशों को नीतिगत बदलावों के बारे में सोचने को विवश कर सकती है, अब समय आ गया है कि सरकार शिक्षा एवं चिकित्सा को लेकर नीतिगत कठोर मानवतापूर्ण बदलाव करें एवं इन्हें मुनाफा कमाने की मशीन न बनने दे। निस्संदेह, भागवत के संदेश पर मोदी सरकार को गंभीरता से विचार-विमर्श करना चाहिए। दरअसल, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बाजार की वस्तु के बजाय नागरिक अधिकारों के दायरे में लाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों को राजस्व स्रोत के बजाय नागरिक दायित्वों के रूप में मानकर सरकार समता, संतुलन एवं सेवा का समाज स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोप से गरमाई बहस, चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल

चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतें पहले भी आती रही हैं, लेकिन आमतौर पर वे किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकीं या फिर निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें निराधार घोषित किया जाता रहा है। अब इस बार जिस गंभीर स्वरूप में इस मामले को उठाया गया है।

रवि जैन

किसी भी देश में लोकतंत्र की मजबूती और विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें सरकार के चुने जाने की प्रक्रिया कितनी स्वच्छ, स्वतंत्र और पारदर्शी है। इसके लिए चुनाव आयोजित कराने वाली संस्था को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न हो, मतदान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तथा चुनाव में हिस्सेदारी करने वाले सभी दलों के लिए भरोसेमंद हो और नतीजों को लेकर सभी पक्ष संतुष्ट हों।

मगर देश में होने वाले अमूमन हर चुनाव के बाद जिस तरह के विवाद सामने आते रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया में गड़बड़ी और इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के समूचे तंत्र के साथ-साथ नतीजों तक को लेकर जैसे सवाल उठे हैं, उससे कई तरह की आशंकाएं खड़ी हुई हैं। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को सार्वजनिक रूप से कई जगहों पर हुए मतदान और उसमें हुई गड़बड़ियों के संदर्भ में चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए हैं, वे अपनी प्रकृति में बेहद गंभीर हैं और स्वाभाविक ही इस पर चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टता की अपेक्षा

की जा रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि लोकसभा चुनावों, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा सामने रखते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर, फर्जी मतदाता, गलत पते, एक पते पर कई मतदाता, एक मतदाता का नाम कई जगह की सूची में होने जैसे कुछ खास तरीकों पर आधारित 'वोट चोरी' करने के इस माडल को कई निर्वाचन क्षेत्रों में अमल में लाया गया, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके।

हालांकि चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतें पहले भी आती रही हैं, लेकिन आमतौर पर वे किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकीं या फिर निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें निराधार घोषित किया जाता रहा है। अब इस बार जिस गंभीर स्वरूप में इस मामले को उठाया गया है, उसके बाद देश भर में यह बहस खड़ी हो गई है कि अगर इन आरोपों का मजबूत आधार है तो इससे एक तरह से समूची चुनाव प्रक्रिया की वैधता कठघरे में खड़ी होती है। इस मसले पर चुनाव आयोग ने फिलहाल कोई जवाब देने के बजाय राहुल गांधी से शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर कर शिकायत देने या फिर देश की जनता को गुमराह न करने को कहा है। मगर राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' का दावा करते हुए जिस तरह अपने आरोपों को सबूतों पर आधारित बताया है, उसके बाद चुनाव आयोग से उम्मीद की जाती है कि वह समूची चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे को बहाल रखने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ इस संबंध में उठे सवालों का जवाब सामने रखे।

अगर वास्तव में कोई गड़बड़ी रही है, तो कमियों को स्वीकार करके उसमें सुधार करना देश के हित में ही होगा। यों भी, मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम हटाने और जोड़ने या फर्जी मतदान के जरिए नतीजों को प्रभावित करने को लेकर हर चुनाव के बाद विवाद खड़े होते रहे हैं। बिहार में जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में भी लाखों मतदाताओं को बाहर किए जाने को लेकर कई सवाल उठे हैं।

ऐसे में समूची चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ मतदान और नतीजों के संबंध में सौ फीसद पारदर्शिता तथा ईमानदारी सुनिश्चित होने को लेकर आम लोगों के बीच भरोसा होना लोकतंत्र के जीवन के लिए जरूरी है।

वोट चोरी के आरोपों की चुनाव आयोग गंभीरता से जांच करे

मतदाता सूची में गड़बड़ी के प्रमाण निरंतर प्रकाश में आ रहे हैं- कहीं एक घर में 250 मतदाता पंजीकृत हैं तो कहीं 10.15 फीट के कमरे में 80 मतदाता रह रहे हैं और वह भी अलग-अलग जातियों व क्षेत्रों के कहीं बड़ी संख्या में मकानों का नंबर शून्य लिखा है, तो कहीं पिता का नाम एफजीएचआई लिखा है या एक ही व्यक्ति को दो फोटो पहचान कार्ड जारी किए हुए हैं, कहीं फॉर्म 6 पर 70 वर्षीय महिला को मतदाता बनाया हुआ है, जबकि इसका संबंध पहली बार के नए मतदाता से है, तो कहीं फोटो ऐसा लगाया हुआ है कि माइक्रोस्कोप से भी दिखायी न दे।

इस किस्म की अनेक त्रुटियां हैं, जिनको त्वरित सुधारने की जरूरत है ताकि मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बना रहे।लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? वह कहीं वोट बढ़ा देता है, कहीं वोट घटा देता है और सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने जवाब में कहता है कि बिहार में मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख लोगों की न तो सूची शेयर करेगा और न ही यह बताने के लिए बाध्य है कि उनका नाम किस वजह से सूची से हटाया गया है।यह जानकारी अगर चुनाव आयोग नहीं देगा, तो फिर कौन देगा?

चुनाव आयोग ने अपनी साईट पर जो बिहार की डिजिटल मतदाता सूची अपलोड की थी उसे हटाकर ऐसे फॉर्मेट में सूची अपलोड की है, जिसे पढ़ना व डाउनलोड करना लगभग असंभव है।

इससे चुनाव आयोग के इरादों पर शक गहरा ही होता है। विशेषकर इसलिए कि 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए जब विपक्ष के 300 सांसदों ने 11 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए समय मांगा, तो उन्होंने जगह की तंगी का हवाला देते हुए केवल 30 सांसदों से ही मुलाकात करने को कहा।

लेकिन यह भी न हो सका, क्योंकि यह सांसद जब संसद भवन से निर्वाचन सदन की तरफ मार्च करते हुए जा रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और दो घंटे बाद छोड़ा क्या मजाक है, देश की राजधानी में इतनी जगह भी नहीं है। ज्ञानेश कुमार 300 सांसदों से एक साथ मुलाकात कर सकें?

मतदाता सूची मामले में देश को गुमराह कर रहा विपक्ष

बिहार ही नहीं देशभर में फर्जी और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के मांग राजनीतिक दल समय समय पर उठाते रहे हैं। बिहार के सीमांचल के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला वर्षों से सामने आ रहा है। पिछले 30 वर्षों में पूरे सीमांचल का समीकरण बदल गया है।

उज्जवल रस्तौगी

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पूरा हो चुका है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक एसआईआर का विरोध जारी है। हालांकि विपक्ष के तीखे विरोध के बीच चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिर्फ असम में भाजपा सरकार है। शेष राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। वे अभी से चौकन्नी हो गई हैं और एसआईआर को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना देना चाहती हैं।

वास्तव में विपक्ष रणनीति के तहत एसआईआर पर देशवासियों को गुमराह कर रहा है। सड़क से संसद तक वो एसआईआर का विरोध कर रहा है, और चुनाव आयोग पर अमर्यादित बयानबाजी से लेकर आरोप तक लगा रहा है। जबकि तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है कि बिहार में एसआईआर का विरोध कर रही पार्टियों ने भी अपने बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए को बढ़-चढ़कर काम में लगाया था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 23 जून को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के पहले कांग्रेस ने केवल 8586 बीएलए लगाए थे। लेकिन 25 जुलाई को प्रक्रिया समापन के वक्त कांग्रेस के 17549 बीएलए नियुक्त रहे। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करने के बावजूद इसके लिए 105 फीसदी बीएलए बढ़ाए।

भाजपा के 53338 बीएलए प्रकिया का हिस्सा बने। राष्ट्रीय जनता दल के 47506 बीएलए प्रक्रिया में शामिल हुए। जनता दल यूनाइटेड के 36550 बीएलए शामिल हुए। लेफ्ट पार्टियों ने एसआईआर प्रक्रिया की शुरूआत में दिलचस्पी नहीं दिखाई लेकिन आखिर तक इन पार्टियों ने भी बीएलए की संख्या बढ़ाई। बिहार में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कुल 1 लाख 60 हजार 813 बीएलए गहन मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बने। किसी तरह की अनियमितता होने पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ता तुरंत अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन अब तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जहां विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत की हो। केवल विपक्ष के नेता ही इस तरह की बात कर सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का असली चेहरा और चरित्र यही है। वो एक और देशवासियों को गुमराह करने और संवैधानिक संस्थाओं की साख को धूमिल करने का कुकृत्य करता है, तो वहीं दूसरी और कानून प्रक्रियाओं में

बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेता है।

बिहार ही नहीं देशभर में फर्जी और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के मांग राजनीतिक दल समय समय पर उठाते रहे हैं। बिहार के सीमांचल के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला वर्षों से सामने आ रहा है। पिछले 30 वर्षों में पूरे सीमांचल का समीकरण बदल गया है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में अल्पसंख्यकों की आबादी 40 फीसदी से 70 फीसदी तक हो चुकी है। यही कारण है कि वर्षों से इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की रोक की मांग उठती रही है। कई इलाकों से हिंदुओं के पलायन की भी खबर उठी थी। केंद्र सरकार ने जब पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कही थी तो बिहार में इस इलाके से भी विरोध के सुर उठे थे।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार के 99.8 फीसदी यानी 7.23 करोड़ मतदाता इस रिवीजन प्रक्रिया में कवर हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि पुनरीक्षण में बिहार में कम से कम 61 लाख मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। इसमें 21.6 लाख मतदाताओं का निधन हो चुका है। 31.5 लाख मतदाता स्थाई तौर पर दूसरे स्थानों-शहरों में बस गए हैं। हैं। लगभग सात लाख मतदाताओं के नाम दो स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज हैं।

बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। विधानसभाओं में कुछ सौ मतदाताओं का अंतर ही जीत-हार पर असर डाल देता है। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में करीब बीस प्रतिशत सीटों पर जीत और हार का अंतर महज ढाई फीसद तक ही था। इनमें से 17 सीटों पर जीत तो एक प्रतिशत के कम वोट से ही हुई थी। अगर गहन पुनरीक्षण में इन मतदातओं के नाम नहीं काटे गए तो उनके नाम पर चुनावी नतीजों को बदला जा सकता है।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। हालांकि देश की राजनीति के लिए यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी राजनीतिक दल ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी हो। इससे पहले भी जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में अनेक बार कुछ राजनीतिक दलों और अतिवादी संगठनों ने चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी। आपातकाल के बाद भी प्रमुख विपक्षी दलों ने चुनाव के बहिष्कार करने की बात की थी। हालांकि इसके बावजूद वहां चुनाव हुए और उन सभी लोगों ने चुनाव में हिस्सा भी लिया और जीत हासिल की।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का मुद्दा अपनी स्टाइल में उठा रहे हैं। वो केंद्र की बीजेपी सरकार पर 'वोटों की चोरी' का आरोप लगा रहे हैं। वोटिंग में गड़बड़ी का इल्जाम तो राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगाने लगे थे, लेकिन अब ज्यादा जोरदार तरीके से उसे उठा रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बाकी चुनावों के मामले चुप्पी साध लेते हैं।

राहुल गांधी पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग पर तल्ख, अमर्यादित और अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। आयोग पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। असल में राहुल गांधी चुनाव आयोग और चुनाव मशीनरी को दबाव में लेना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुले मंच से यह घोषणा कर चुकी हैं कि वे बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी। विपक्ष के कई दूसरे नेता भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान मोहब्बत की दुकान, संविधान की रक्षा और संविधान की कॉपियां लेकर देशभर में घूमते थे। और भाजपा पर संविधान विरोधी होने और संविधान बदलने का आरोप लगाते थे। यही इनका मूल चरित्र है।

2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने भाजपा के सत्ता में आने के बाद 'संविधान बदलने का खतरा' होने का मुद्दा उठाया था। इससे कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी। उसी तरह विपक्ष लोगों के बीच वोट खोने का डर और चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर बढ़त हासिल करना चाहता है। इससे वह सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने के साथ-साथ जनता के बीच अपनी पकड़ भी मजबूत करना चाहता है। यदि जनता के एक प्रतिशत लोगों के मन में भी अपना 'वोट खोने का डर' पैदा हो जाता है तो इससे पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल पूरी तैयारी के साथ इसी 'रणनीति' पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

चुनाव आयोग ने केवल दूसरी जगह चले गए मतदाताओं, मृतकों और एक ही व्यक्ति के दो स्थानों पर मतदाता सूची में शामिल होने वाले मतदाताओं का नाम ही मतदाता सूची से हटाने की बात कही है, ऐसे में एसआईआर का विरोध पूरी तरह से अतार्किक है।

चुनाव आयोग नियम कानून के तहत वोटर लिस्ट अपडेट कर रहा है। यह उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वच्छ और स्पष्ट मतदाता सूची जरूरी है। वास्तव में, मतदाता सूची पर विपक्ष का हंगामा केवल राजनीतिक स्टंट कर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश है। विपक्ष चुनावों में अपनी हार को देखकर अभी से बहाने की तलाश कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन और चुनाव आयोग पर बयानबाजी उसी का नतीजा है।

भारत के उद्योग जगत में ऐतिहासिक दिन

नोएडा में कॉर्निंग द्वारा निर्मित भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन

वेलकम इंडिया

भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया, जब केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया।

ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड के साथ साझेदारी में स्थापित यह संयंत्र, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 'इंजीनियर्ड बाय कॉर्निंग' ब्रांड के तहत उच्च-गुणवत्ता वाले सुरक्षात्मक ग्लास का निर्माण करेगा। इस इकाई के उत्पाद भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों में उपलब्ध होंगे, जिससे मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण को बल मिलेगा।

मंत्री ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विकास पर प्रकाश डाला

अश्वनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि स्थानीय स्तर पर टेम्पर्ड ग्लास का उत्पादन मोबाइल कंपोनेंट निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य अंततः फोन में इस्तेमाल होने वाले हर पुर्जे का निर्माण करना है, चिप्स से लेकर कवर ग्लास और सर्वर कंपोनेंट्स तक। मंत्री ने यह भी बताया कि पहली मेड इन इंडिया चिप जल्द ही बाजार में आएगी।

उन्होंने बताया कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन एक दशक से भी कम समय में छह गुना बढ़कर ₹11.5 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, जिसमें ₹3 लाख करोड़ का निर्यात और 25 लाख नौकरियाँ सृजित हुई हैं। उन्होंने भारत की डिजाइन प्रतिभा को इसकी सबसे मजबूत संपत्ति बताया और आईआईटी मद्रास के माइक्रोकंट्रोलर नवाचार और अब यूरोप को निर्यात किए जा रहे रेलवे उपकरणों जैसे उदाहरणों का उल्लेख किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेम्पर्ड ग्लास मोबाइल फोन के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है और इसका स्वदेशी निर्माण मेक इन इंडिया की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने आगे कहा कि भारत धीरे-धीरे मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले हर

कंपोनेंट का निर्माण करेगा, जिसमें चिप्स, कवर ग्लास, लैपटॉप और सर्वर कंपोनेंट शामिल हैं, जिससे देश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित होगा।

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि के साथ, उन्होंने एक स्थिर, नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को रेखांकित किया और युवाओं से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 में योगदान देने का आह्वान किया।

निवेश, क्षमता और भविष्य का विस्तार

नोएडा संयंत्र की शुरूआत ₹70 करोड़ के निवेश से हुई है, जिससे पहले चरण में सालाना 2.5 करोड़ यूनिट उत्पादन की क्षमता प्राप्त होगी और 600 से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। दूसरे चरण में, अतिरिक्त ₹800 करोड़ का निवेश करके उत्पादन को सालाना 20 करोड़ यूनिट तक बढ़ाया जाएगा और 4,500 से ज्यादा नए रोजगार सृजित किए जाएँगे।

यह संयंत्र उन्नत क्षमताओं से सुसज्जित है, जिनमें स्क्राइबिंग, शेपिंग, पॉलिशिंग, दो-चरणीय धुलाई, रासायनिक टेम्परिंग, कोटिंग, प्रिंटिंग और लेमिनेशन शामिल हैं, और ये सभी कठोर गुणवत्ता जाँच के अधीन हैं। अकेले भारत का घरेलू टेम्पर्ड ग्लास बाजार लगभग ₹20,000 करोड़ मूल्य का 500 मिलियन से अधिक टुकड़ों का अनुमानित है, जबकि वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र का मूल्य 60 बिलियन डॉलर से अधिक है, जो अवसरों की व्यापकता को दर्शाता है।

भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का शुभारंभ दर्शाता है कि कैसे स्थानीय विनिर्माण फोन और सेमीकंडक्टर से आगे बढ़कर प्रमुख सहायक उपकरणों तक भी पहुँच रहा है। मजबूत सरकारी समर्थन, महत्वपूर्ण निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ, यह पहल आयात पर निर्भरता कम करने, निर्यात को मजबूत करने और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए तैयार है।

मेक इन इंडिया विजन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण: अशोक कुमार गुप्ता

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष, अशोक कुमार गुप्ता ने इस ऐतिहासिक अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आईसीईए, कॉर्निंग और सभी सहयोगियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में गर्व से भरा हुआ कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के विजन को 'लोकल फॉर ग्लोबल' में बदलने की दिशा में यह परियोजना एक अहम मील का पत्थर साबित होगी। यह सफलता न सिर्फ भारतीय उद्योग के लिए, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं के लिए भी ऐतिहासिक है। नोएडा से शुरू हुआ यह नया अध्याय अब पूरी दुनिया में भारत की ताकत और क्षमता का अहसास कराएगा। अशोक कुमार गुप्ता ने कहा, 'यह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग और मेक इन इंडिया विजन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन बाजारों में से एक होने के बावजूद, भारत टेम्पर्ड ग्लास के लिए आयात पर निर्भर रहा है। इस पहल के साथ, हम सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का समर्थन करने के लिए वैश्विक स्तर की क्षमताओं का निर्माण करना चाहते हैं। हमारी आकांक्षा है कि प्रत्येक भारतीय मोबाइल फोन उपयोगकर्ता अपनी स्क्रीन की सुरक्षा के लिए BIS प्रमाणन और फॉग मार्किंग वाले मेक इन इंडिया टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग करे।'

योगी सरकार के प्रयासों से देश-विदेश में खुल रहे रोजगार के अवसर

विदेश से लेकर स्थानीय सेवाओं तक, श्रम एवं सेवायोजन विभाग की योजनाएं युवाओं को दे रही हैं नई दिशा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक पहल कर रही है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग की योजनाएं जिस दूरदर्शिता से रोजगार सृजन की बहुआयामी रणनीति अपनाई है। रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार की नीति अब सिर्फ स्थानीय नौकरियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की शुरूआत की है। मिशन के मुख्य उदेश्यों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोजगार के अवसरों

मुकुल पंडित

को पता लगाना, स्किलगैप का अध्ययन कर उसको दूर कराना, रोजगार कार्यक्रम संचालित करना, कॅरियर काउन्सिलिंग कराना तथा राज्य के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों एवं अल्परोजगार युवाओं को पोस्ट प्लेसमेन्ट स्पोर्ट प्रदान करना है जिसमें घरेलू एवं विदेशी प्लेसमेन्ट द्वारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो। विदेश में नौकरी के लिए युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से युवाओं को प्रोफेशनल रूप से तैयार किया जायेगा तथा बाजार मांग के अनुरूप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किये जाएंगे।

जापान, जर्मनी, क्रोएशिया और UAE में श्रमिकों की भारी मांग

इस अभियान को और विस्तार देते हुए प्रदेश सरकार ने जापान, जर्मनी, क्रोएशिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से भी नर्सों, केयर गिवर्स,

10,830 रोजगार मेलों के माध्यम से 13,64,501 अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली

रोजगार सृजन को लेकर प्रदेश सरकार की दूसरी बड़ी उपलब्धि रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाना है। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक सेवायोजन विभाग द्वारा आयोजित 10,830 रोजगार मेलों के माध्यम से 13,64,501 अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में नौकरियां मिली हैं। ये मेले राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित किए गए, जिनमें सैकड़ों कंपनियों ने हिस्सा लिया और युवाओं को मौके पर ही चयनित कर नौकरी दी। इससे न केवल युवाओं को अवसर मिले बल्कि कंपनियों को भी प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति उपलब्ध हुई। इस मिशन के तहत अब तक 5,978 श्रमिकों को इजराइल में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं, 1,383 और निर्माण श्रमिकों को भेजने की प्रक्रिया तेजी से प्रगति पर है। इस प्रयास से राज्य में न केवल विदेशी मुद्रा का आगमन बढ़ेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अनुमान है कि इजराइल भेजे गए श्रमिकों से प्रदेश को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का रेमिटेन्स प्राप्त हो सकता है, जो ह्यवन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थाह्ल के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। योगी सरकार का मानना है कि केवल नौकरी उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि युवाओं को सही दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के तहत सेवायोजन विभाग द्वारा अबतक 24,493 करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 26,51,727 युवाओं को करियर मार्गदर्शन मिला। इन कार्यक्रमों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, जहां जानकारी की कमी के कारण प्रतिभाएं पीछे छूट जाती थीं।

ड्राइवरों और निर्माण श्रमिकों की मांग प्राप्त की है। इसमें लगभग 1.50 लाख रुपए तक का वेतन मिलेगा, साथ ही खाड़ी देशों से भी विभिन्न सेक्टर की रिक्तियों की प्राप्ति सम्भावित है। श्रम विभाग इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है ताकि उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सम्मानजनक और बेहतर वेतनमान वाली नौकरियां मिल सकें। यह पहल युवाओं को विदेश जाने का सुरक्षित और कानूनी विकल्प उपलब्ध कराकर अवैध माध्यमों पर भी रोक लगाने में सहायक है।

सेवामित्र पोर्टल पर 52,349 श्रमिक पंजीकृत

स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने 'सेवामित्र योजना' की शुरूआत की है। इस योजना के अंतर्गत कुशल कामगारों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर अब तक 52,349 श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। ये श्रमिक प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, एसी मैकेनिक, ब्यूटीशियन आदि सेवाओं के लिए लोगों को घर बैठे उपलब्ध हो रहे हैं। यह योजना एक ओर जहां श्रमिकों की आय सुनिश्चित कर रही है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश अब केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि श्रम और प्रतिभा का निर्यात करने वाला राज्य बन रहा है। आने वाले वर्षों में यह पहल राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

- **विदेशों में नौकरी की चाबी बना यूपी का रोजगार मिशन, जापान, जर्मनी, क्रोएशिया और यूएई में श्रमिकों की भारी मांग**
- **योगी सरकार के मेले ने बदली युवाओं की तकदीर, 10,830 रोजगार मेलों से 13.64 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में मिला काम**
- **सेवायोजन द्वारा 26.5 लाख अभ्यर्थियों को मिला मार्गदर्शन, 24 हजार से ज्यादा काउंसिलिंग सत्र आयोजित**
- **सेवामित्र से 52,000 से अधिक कुशल कामगारों को मिला स्थानीय स्तर पर रोजगार का प्लेटफॉर्म**

अपराधियों के हौसले बढ़ाती डिजिटल तकनीक

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन साल में ही ठगी के नए अवतार से ठगी की राशि 20 गुणा बढ़ गई है। 2025 के शुरूआती दो महीनों में ही 17 हजार 718 से अधिक मामलों में 210 करोड़ 21 लाख रु. से अधिक की ठगी हो चुकी है।

कपिल चौहान

राजस्थान के जोधपुर जिले के मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपराधियों ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए 20 लाख रु. की मांग पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर दो कथित अपराधियों को पकड़ा है। मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसकी कामेडियन पत्नी को उनके अश्लील वीडिया वायरल करने की धमकी दी गई। खैर यह तो इन्होंने हिम्मत दिखाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी अन्यथा देश दुनिया में इस तरह की धमकियां देकर डरा-धमकाकर वसूली करने के अपराधों की बाढ़ से आ गई है। दरअसल डिजिटल तकनीक का अपराधियों द्वारा अपराध में उपयोग आम होता जा रहा है। डिजिटल तकनीक के कारण अपराधियों के बढ़ते हौसले की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट ने एक महिला की निजी तस्वीरों को वाट्सएप पर सार्वजनिक करने के मामलें में जमानत देने से इंकार करते हुए सख्त टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति भनोट ने 2023 में भी सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो अपालोड के प्रकरण में गंभीर टिप्पणी की थी। दरअसल डिजिटल क्रांति ने अपराध की दुनिया में भी बड़ी सेंध लगा ली है। अपराधी विभिन्न माध्यमों से डिजिटल तकनीक का उपयोग कर गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। कम्प्यूटर, कम्प्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस, डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट आदि के माध्यम से नित नए अपराध की तरीके अपना रहे हैं। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का खासतौर से इस्तेमाल करते हुए लोगों की निजी जिंदगी को प्रभावित करने के साथ ही डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगी जैसे गंभीर अपराध बेखौफ कर रहे रहे हैं। मजे की बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट या बैंक अकाउंट ठगी के शिकार होने वाले अधिकतर लोग अच्छे पढ़े-लिखे, समाज में अच्छे पदों से सेवानिवृत या यों कहे कि समझदार लोग ही अधिक शिकार हो रहे है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि वे साइबर ठगी के शिकार होते होते बचे हैं। डिजिटल तकनीक से अपराध करने वालों के हौसलों को देखिये कि कुछ घंटों नहीं अपितु कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रख कर हजारों नही बल्कि लाखों रुपए अपने खातों में ड़लवा रहे हैं। यह सब तो तब है जब कि सरकार मोबाइल टोन के समय ही ओपनिंग मैसेज के माध्यम से आगाह कर रहे हैं पर इस सबके बाजवूद इस तरह की घटनाओं में साल दर साल मल्टीपल बढ़ोतरी हो रही है।

1970 से 1990 के दो दशकों में केविन

मिटनिक और उनके साथियों ने मोटोरोला, नोकिया आदि के नेटवर्क में सेंध मारना शुरू कर दिया था। बॉब थामस ने क्रीपर वायरस के माध्यम से कम्प्यूटर सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद तो समय समय पर वायरसों द्वारा कम्प्यूटर सिस्टम को हैंक या प्रभावित करने का सिलसिला ही चल निकला।

कम्प्यूटर आधारित अपराधों का केवल अमेरिका का 2015 का आंकड़ा ही चौकाने वाला है जिसमें एफबीआई के अनुसार 2 लाख 88 हजार से भी अधिक शिकायतों के साथ ही केवल एक वर्ष में 445 अरब डॉलर के नुकसान का दावा किया गया। साइबर ठगी के मामलों में रशिया पहले पायदान पर तो यूक्रेन दूसरे पायदान पर है। चीन, अमेरिका, नाइजेरिया और रोमानिया का नंबर आता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है साइबर ठगों के सारी दुनिया में हौसले बुलंद है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन साल में ही ठगी के नए अवतार से ठगी की राशि 20 गुणा बढ़ गई है। 2025 के शुरूआती दो महीनों में ही 17 हजार 718 से अधिक मामलों में 210 करोड़ 21 लाख रु. से अधिक की ठगी हो चुकी है। साल 2022 में साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट या इस तरह की ब्लेक मेलिंग, ऑनलाइन ठगी आदि के 39925 मामलों में 91 करोड़ 14 लाख की ठगी हुई थी जो एक साल बाद ही 2023 में बढ़कर 60676 हो गई और इसमें 339 करोड़ रु. की राशि की ठगी हो गई। लाख प्रयासों के बावजूद 2024 में एक लाख 23 हजार 672 मामलों में 1935 करोड़ 51 लाख रु. की ठगी हो गई।

यह तो वे मामलें हैं जो पुलिस में दर्ज हुए हैं जबकि हजारों मामलें ऐसे भी होंगे जिनमें मामलें दर्ज कराए ही नहीं गए होंगे। खास बात यह है कि ठगी के केन्द्र व ठगी के तरीके से वाकिफ होने के बावजूद यह होता जा रहा है। हांलाकि झारखण्ड के जमातड़ा से ठगों के तंत्र को तोड़ दिया गया पर देश में एक दो नहीं अपितु 74 जिलों में इस तरह की ठगी करने वालों के हॉटस्पॉट विकसित हो गए। झारखण्ड, राजस्थान, हरियाणा और बिहार के केन्द्र पहले पांच प्रमुख सेंटर विकसित हो गए।

हैंकिंग, रेनसमवेयर, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ब्लैक मेलिंग अपराधियों के प्रमुख हथियार है। व्यक्ति को इस तरह से सम्मोहित व भयग्रस्त कर देते हैं कि समझदार और पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसा गंवा बैठते हैं। ठगी, जबरन वसूली, पोर्नोग्राफी, बाल पोर्नोग्राफी, धनशोधन, औद्योगिक जानकारी चुराने, ड्रग, ब्लेक मेलिंग, ड़राने-धमकाने सहित विभिन्न तरह के अपराध को अंजाम देने में इन्होंने विशेषज्ञता हासिल कर ली है। लोगों की गाढ़ी कमाई को हजम करने में इन्हें विशेषज्ञता हासिल है। लोगों की कमजोरी को यह समझते हैं और उसी कमजोरी के चलते पढ़े लिखे और हौशियार लोगों को भी आसानी से ठगी का शिकार बना लेते हैं। जाल ऐसा कि यह समझते हुए कि ऐसा आसानी से होता नहीं है फिर भी चक्कर में फंस ही जाते हैं और ठगों के आगे सरेण्डर होकर लुट जाते हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि डिजिटल तकनीक ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया हैं। तकनीक ने समझ और संवाद को आसान बनाया है। जानकारी का पिटारा खोला है। पर इसके साइड इफेक्ट के रुप में अपराधियों के जाल भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में तकनीक का सकारात्मक उपयोग हो इसके लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। साइबर कानून और साइबर थाने बना देने मात्र से समस्या का समाधान होने वाला नहीं हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम के बावजूद जिस तरह से हजारों लोग प्रतिदिन साइबर अपराधियों के आसानी से शिकार कार बन रहे हैं।

देखा जाए तो डिजिटल ठगी करने वाले पूरी तकनीक और सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में डिजिटल अपराध और अपराधियों से लोगों को बचाने की कोई ना कोई फूलप्रुफ तकनीक व व्यवस्था बनानी ही होगी।

ऐसे बदरंग हालातों में यह सवाल रह-रहकर सिर उठाने लगता है कि आखिर कैसी है ये आजादी ? आखिर आजादी का अर्थ क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि यह न जान लिया जाए कि स्वतंत्र होना आखिर कहते किसे हैं ?

आजादी के 78 वर्षों में कितने बदले लोकतंत्र के हालात ?

प्रत्येक भारतवासी के लिए 15 अगस्त का दिन गौरव का दिन है क्योंकि इसी दिन भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिली थी। हालांकि स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज भी देश के प्रत्येक नागरिक के दिलोदिमाग में वही जज्बा और उत्साह समाहित है लेकिन जब हर वर्ष स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे के नीचे खड़े होकर बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधियों को देश की रक्षा व प्रगति का संकल्प लेते देखते हैं, जो वर्षभर सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते देखे जाते हैं तो मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसी संकल्प अदायगी से देश को हासिल क्या होता है ? देश को आजाद हुए सात दशक से अधिक हो चुके हैं लेकिन आजादी के इन 78 वर्षों में लोकतंत्र के पवित्र स्थल संसद और विधानसभाओं के हालात किस कदर बदले हैं, वह

चरण सिंह

किसी से छिपा नहीं है, जहां अभद्रता की सीमा पार करते जनप्रतिनिधि गाली-गलौच, उठापटक से लेकर कुर्ता-फाड़ राजनीति तक उतर आते हैं। विधानसभाओं की तो क्या बात करें, जब संसद की कार्यवाही ही कभी विपक्ष और कभी स्वयं सत्ता पक्ष द्वारा ही कई-कई दिनों तक लगातार नहीं चलने दी जाए तो राष्ट्र के लिए इससे ज्यादा चिंतनीय स्थिति और क्या हो सकती है ? संसद में होने वाले ऐसे हंगामों के कारण प्रति मिनट आम आदमी के करीब ढ़ाई लाख रुपये बर्बाद होते हैं यानी हर एक घंटे में करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होते हैं। अब चूंकि संसद की कार्यवाही प्रतिदिन 6 घंटे चलनी होती है, ऐसे में संसद के दोनों सदनों में दोनों पक्षों के विरोध, हो-हल्ले और शोर के कारण जनता के खून-पसीने की कमाई के प्रतिदिन करीब 9 करोड़ रुपये से अधिक बर्बाद हो जाते हैं।

गंभीर चिंतन का विषय है कि वर्षों की गुलामी के बाद मिली आजादी को आज हम जिस रूप में संजोकर रख पाए हैं, वह 78 वर्षों में ही कितना विकृत हो चुका है। आजादी के दीवानों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस देश को आजाद कराने के लिए वे इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, वहां कुछ दशकों में ही आजादी की तस्वीर ऐसी हो जाएगी। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने विकास के

मार्ग पर तेजी से कदम बढ़ाए और विकास के अनेक सोपान तय किए हैं। तकनीकी कौशल हासिल करते हुए देश अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है और चांद पर भी तिरंगा लहरा दिया है। लेकिन महिलाओं से दुर्व्यवहार की लगातार बढ़ती घटनाएं और समाज में अपराधों की बढ़ती सीमा को देख बुजुर्ग तो अब कहने लगे हैं कि गुलामी के दिन तो आज की आजादी से कहीं बेहतर थे, जहां अपराधों को लेकर मन में भय तो व्याप्त रहता था किन्तु कड़े कानून बना दिए जाने के बावजूद अपराधियों के मन में अब किसी तरह का भय नहीं दिखता। 'सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का' कहावत हर कहीं चरितार्थ हो चली है। देश के कोने-कोने से सामने आते अबोध बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के बढ़ते मामले आजादी की बेहद शर्मनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई है, ऐसे मामलों को देखते हुए और क्या कहा जाए? देश में महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रही है, आतंकवाद की घटनाएं पग पसार रही हैं, आरक्षण की आग रह-रहकर देश को जलाती रहती है। इस तरह के हालात निश्चित तौर पर देश के विकास के मार्ग में बाधक बनते हैं। हर कोई सत्ता के इर्द-गिर्द राजनीतिक रोटियां सेंकता नजर आ रहा है, कोई सत्ता बचाने में लगा है तो कोई गिराने में। संसद और विधानसभाओं में हंगामे आए दिन की बात हो गई है। आजादी के बाद सामाजिक और आर्थिक पहलू पर देश में कमजोर तबके का स्तर सुधारने की नीयत से लागू आरक्षण के राजनीतिक रूप ने देश को आज उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां समूचा देश रह-रहकर जातीय संघर्ष के बीच उलझता दिखाई देता है। स्वार्थपूर्ण राजनीति ने माहौल को इस कदर विकृत कर दिया है, जहां से निकल पाना संभव ही नहीं दिखता। राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो या गुजरात अथवा महाराष्ट्र, आरक्षण के नाम पर उठते विध्वंसक आन्दोलनों की आग में से जब-तब बुरी तरह झुलसते रहे हैं और हर कोई इस तरह के परिवेश का राजनीतिक लाभ लेने की कवायद में जुटा नजर आता है। आजादी के बाद के इन करीब साढ़े सात दशकों में भ्रष्टाचार और अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। बगैर लेन-देन के प्रायः कोई कार्य सम्पन्न नहीं होता। बड़े नेता की तो कौन कहे, छुटभैया नेताओं की भी चांदी हो चली है। आजादी के बाद लोकतंत्र के इस बदलते स्वरूप ने आजादी की मूल भावना को बुरी तरह तहस-नहस कर डाला है। यह आजादी का एक शर्मनाक पहलू ही है कि गिने-चुने मामलों को छोड़कर हत्या, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों से विभूषित जनप्रतिनिधि अक्सर सम्मानित जिंदगी जीते रहते हैं। देश के ये बदले हालात आजादी के कौनसे स्वरूप को उजागर कर रहे हैं, विचारणीय है।

ऐसे बदरंग हालातों में यह सवाल रह-रहकर सिर उठाने लगता है कि आखिर कैसी है ये आजादी? आखिर आजादी का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि यह न जान लिया जाए कि स्वतंत्र होना आखिर कहते किसे हैं? देश को? व्यक्ति को? समाज को? यह जानना भी जरूरी है कि क्या कुछ बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित व्यक्ति, समाज या देश को स्वतंत्र कहा जा सकता है? क्या भोजन, कपड़ा और रहने की व्यवस्था, बीमारी से बचाव, भय-आतंक, शोषण व असुरक्षा से छुटकारा, साक्षर एवं शिक्षित होने के पर्याप्त अवसर मिलना और अन्य ऐसी ही कई बातें मानव के बुनियादी अधिकार नहीं हैं? क्या शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति के संघर्ष को मानव का बुनियादी अधिकार नहीं माना जाना चाहिए? लोकतंत्र के हाशिये पर खड़ी देश की जनता को इस दिशा में फिर से मंथन करना आवश्यक हो गया है कि वह किस तरह की आजादी की पक्षधर है? आज की आजादी, जहां तन के साथ-साथ मन भी आजाद है, सब कुछ करने के लिए, चाहे वह वतन के लिए अहितकारी ही क्यों न हो, या उस तरह की आजादी, जहां वतन के लिए अहितकारी हर कदम पर बंदिश हो। आज की आजादी, जहां स्वहित राष्ट्रहित से सर्वोपरि होकर देशप्रेम की भावना को लीलता जा रहा है, या वह आजादी, जहां राष्ट्रहित की भावना सर्वोपरि स्वरूप धारण करते हुए देश को आजाद कराने में गुमनाम लाखों शहीदों के मन में उपजे देशप्रेम का जज्बा सभी में फिर से जागृत कर सके। इस तरह के परिवेश पर सभी देशवासियों को आजादी के इस पावन पर्व पर सच्चे मन से मंथन कर सही दिशा में संकल्प लेने की भावना जागृत करनी होगी, तभी आजादी के वास्तविक स्वरूप को परिलक्षित किया जा सकेगा।

एसीपी भास्कर वर्मा की पुलिसिंग के आला अफसर भी कायल

प्रवीण सिंह कुशवाहा

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जनपद के एक गाँव में किसान राजकुमार वर्मा के घर एक पुत्री के बाद साल 1981 में जब पुत्र का जन्म हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। परंतु नियति ने तो ठान रखा था कि साधारण से किसान के घर जन्मा यह बालक भविष्य में ना केवल अपने परिवार का सिर गर्व से ऊँचा करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एक अधिकारी की वर्दी पहनकर अपराधियों के दिलों में खौफ भी पैदा करेगा। वेलकम इंडिया में इस बार हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐसे ही एक जाँबाज अधिकारी और वर्तमान में कविनगर एसीपी भास्कर वर्मा से।

सुलतानपुर जनपद के मूल निवासी भास्कर वर्मा शुरू से ही होनहार रहे हैं। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। तीन बहनों के इकलौते भाई भास्कर वर्मा के साथ भी ऐसा ही था। उनकी प्रतिभा को देखकर भास्कर वर्मा के पिता और साधारण से किसान राजकुमार वर्मा ने अपने बेटे को राजकीय उच्च स्तरीय विद्यालय, रायबरेली में दाखिला दिलवा दिया। तत्पश्चात् इंटरमीडिएट की पढ़ाई लखनऊ से करने के बाद भास्कर वर्मा ने देश के ख्याति प्राप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिला ले लिया। यहाँ उन्होंने स्नातक के साथ-साथ एनसीसी में भी विशेष रुचि ली और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ एनसीसी का तीन वर्षीय सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया।

भास्कर वर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद यहीं एलएलबी कोर्स में दाखिला ले लिया। साल 2007 में एलएलबी की पढाई पूरी करने के पश्चात वकालत में हाथ आजमाने के साथ ही उनके मन में पुलिस अधिकारी बनने की ललक जाग उठी और वो इसकी तैयारियों में लग गए। साल 2013 आते-आते भास्कर वर्मा की मेहनत रंग लाई और उनका चयन पीपीएस अधिकारी के तौर पर हो गया। भास्कर वर्मा के चयन से उनके पूरे परिवार का सीना चौड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रशिक्षण के पश्चात पीपीएस अधिकारी की वर्दी पहने भास्कर वर्मा की पहली पोस्टिंग औरैया जनपद में हुई थी। भास्कर वर्मा ने इस पोस्टिंग के बाद से ही अपनी प्रतिभा का ऐसा लोहा मनवाना शुरू किया जो अभी तक बदस्तूर जारी है।

एसीपी भास्कर वर्मा की प्रतिभा का ही परिणाम था कि साल 2022 में उन्हें गाजियाबाद जैसे अहम जनपद में तैनाती का मौका मिला। 4 दिसंबर 2022 को गाजियाबाद आने के बाद से ही भास्कर वर्मा ने यहाँ अपनी एक खास पहचान कायम कर ली है। भास्कर वर्मा अभी तक यहाँ जिस सर्कल में भी रहे हैं वहाँ अपने हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वहाँ के आम नागरिकों के बीच अपनी खास पहचान कायम कर चुके हैं। भास्कर वर्मा की जादूई शख्सियत का ही परिणाम है कि आम लोगों के बीच तो उनकी छवि एक नेकदिल पुलिस अधिकारी की है जबकि अपराधी उनके नाम से खौफ खाते हैं।

एसीपी भास्कर वर्मा केवल पुलिसिंग के लिए ही नहीं पहचाने जाते बल्कि सामाजिक कार्यों में भी वो बढ़ चढ़ कर शामिल रहते हैं। चाहे कोरोना काल हो या गाजियाबाद में हिंडन नदी में आई बाढ़ हो भास्कर वर्मा ने यहाँ के लोगों की जमकर मदद की। भास्कर वर्मा ने कोरोना के दौरान गाजियाबाद में व्यापारियों की मदद से चल रहे सेवा कार्यों में खूब सहयोग दिया था।

दो वर्ष पूर्व गाजियाबाद के करेहड़ा क्षेत्र में आई बाढ़ के समय साहिबाबाद के एसीपी रहे भास्कर वर्मा का मानवीय चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने आया था। एसीपी रैंक का अधिकारी भास्कर वर्मा अपनी पैंट को घुटने तक मोड़ कर बाढ़ के दौरान कई दिनों तक नंगे पैर बाढ़ के पानी में खड़ा होकर बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करता दिखाई दिया। भास्कर वर्मा को देखकर लोगों के बीच पुलिस अधिकारी की मानवीय छवि उभर कर सामने आई थी और लोगों ने उनकी ना केवल

जमकर सराहना की थी बल्कि ढेरों आशीर्वाद भी दिए थे।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कोरिडोर के उद्घाटन में भास्कर वर्मा की विशेष तैनाती रही थी और इसमें भी उन्होंने उत्कृष्ट कार्य की छाप छोड़ी थी। हालांकि पुलिस अधिकारी की व्यस्त जीवन शैली में समय निकालना बेहद मुश्किल भरा कार्य है परंतु जब कभी उन्हें समय मिलता है तो वो अपनी रुचियाँ और शोक पूरे करने की कोशिश करते हैं। भास्कर वर्मा को पुराने गाने सुनने के साथ ही पुस्तकें पढ़ने का भी बेहद शौक है। भास्कर वर्मा को जब भी समय मिलता है तो वो पुस्तकें पढ़ने के साथ ही पुराने गाने सुनकर अपना समय व्यतीत करते हैं। इसके अलावा एसीपी भास्कर वर्मा पर्यावरण के प्रति भी बेहद सचेत रहते हैं और अपने आसपास पेड़-पौधे लगाना भी उन्हें बेहद पसंद है। एसीपी भास्कर वर्मा के विषय में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एक साधारण से किसान परिवार से आया व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहकर लोगों को उनके दुख-दर्द से निजात दिलवाने का कार्य कर रहा है।

पुलिसिंग के साथ भास्कर वर्मा सामाजिक कार्यों में भी लेते हैं विशेष रुचि

एसीपी भास्कर वर्मा केवल पुलिसिंग के लिए ही नहीं पहचाने जाते बल्कि सामाजिक कार्यों में भी वो बढ़ चढ़ कर शामिल रहते हैं। चाहे कोरोना काल हो या गाजियाबाद में हिंडन नदी में आई बाढ़ हो भास्कर वर्मा ने यहाँ के लोगों की जमकर मदद की। भास्कर वर्मा ने कोरोना के दौरान गाजियाबाद में व्यापारियों की मदद से चल रहे सेवा कार्यों में खूब सहयोग दिया था। दो वर्ष पूर्व गाजियाबाद के करेहड़ा क्षेत्र में आई बाढ़ के समय साहिबाबाद के एसीपी रहे भास्कर वर्मा का मानवीय चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने आया था। एसीपी रैंक का अधिकारी भास्कर वर्मा अपनी पैंट को घुटने तक मोड़ कर बाढ़ के दौरान कई दिनों तक नंगे पैर बाढ़ के पानी में खड़ा होकर बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करता दिखाई दिया। भास्कर वर्मा को देखकर लोगों के बीच पुलिस अधिकारी की मानवीय छवि उभर कर सामने आई थी और लोगों ने उनकी ना केवल जमकर सराहना की थी बल्कि ढेरों आशीर्वाद भी दिए थे। यह कहना बेमानी नहीं होगा कि एसीपी भास्कर वर्मा जैसे अधिकारी ही पुलिस की छवि में चार चाँद लगाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

भास्कर वर्मा ने साधारण से किसान परिवार से किया है पीपीएस का सफर तय

एसीपी भास्कर वर्मा मुंह में चाँदी की चम्मच लेकर पैदा हुए लोगों में से नहीं हैं। शायद उनकी यही पृष्ठभूमि भास्कर वर्मा को जमीन से जुड़े रहकर आम नागरिकों से बेहतर संवाद कायम करने के लिए प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जनपद के एक गाँव में किसान राजकुमार वर्मा के घर एक पुत्री के बाद साल 1981 में जब पुत्र का जन्म हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। परंतु नियति ने तो ठान रखा था कि साधारण से किसान के घर जन्मा यह बालक भविष्य में ना केवल अपने परिवार का सिर गर्व से ऊँचा करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एक अधिकारी की वर्दी पहनकर अपराधियों के दिलों में खौफ भी पैदा करेगा। सुलतानपुर जनपद के मूल निवासी भास्कर वर्मा शुरू से ही होनहार रहे हैं। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। तीन बहनों के इकलौते भाई भास्कर वर्मा के साथ भी ऐसा ही था। उनकी प्रतिभा को देखकर भास्कर वर्मा के पिता और साधारण से किसान राजकुमार वर्मा ने अपने बेटे को राजकीय उच्च स्तरीय विद्यालय, रायबरेली में दाखिला दिलवा दिया। तत्पश्चात इंटरमीडिएट की पढ़ाई लखनऊ से करने के बाद भास्कर वर्मा ने देश के ख्याति प्राप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिला ले लिया। यहाँ उन्होंने स्नातक के साथ-साथ एनसीसी में भी विशेष रुचि ली और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ एनसीसी का तीन वर्षीय सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया। स्नातक के बाद भास्कर वर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही एलएलबी की और फिर यूपीएससी की तैयारी कर साल 2013 में पीपीएस परीक्षा पास की। वर्तमान में गाजियाबाद में कविनगर के एसीपी भास्कर वर्मा की पुलिस अधिकारी के तौर पर पहली तैनाती औरैया जनपद में हुई थी।

भारत को सनातन ने नहीं, विदेशी आक्रांताओं और कांग्रेस ने बर्बाद किया

भारतीय पृष्ठभूमि वाली दुनिया की सबसे पुरातन सभ्यता-संस्कृति 'सनातन धर्म' पर सियासी वजहों से जो निरंतर हमले हो रहे हैं, उनका समुचित जवाब देने में अब कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अन्यथा इसकी सार्वभौमिक स्थिति और महत्ता को दरकिनार करने वाले ऐसे ही बेसिरपैर वाले क्षुद्र सवाल उठाए जाते रहेंगे।

हाल ही में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और अवसरवादी क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी शरद पवार के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक नया विवाद छेड़ते हुए जो कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया और इसकी विचारधारा को विकृत बताया, वह निहायत ही बेहूदगी भरी, अपरिपक्व और पूर्वाग्रह ग्रसित बयानबाजी है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। वहीं, भारत की

अनिल वशिष्ठ

आत्मा समझी जाने वाली सनातन सभ्यता-संस्कृति पर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उनकी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करते हुए उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए, अन्यथा चुनाव आयोग को ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे सम्बन्धित राजनीतिक दल की मान्यता अविलंब समाप्त की जानी चाहिए।

अन्यथा जनमानस में यही संदेश जाएगा कि भारतीय संविधान के मातहत जारी कार्यपालिका प्रशासन और न्यायपालिका प्रशासन में धर्मनिरपेक्षता की पक्षधरता करने वाले ऐसे ऐसे सनातन विरोधी लोग बैठे हैं, जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता-संस्कृति के हमलावरों पर भी उसी तरह से उदार हैं, जैसे कभी मुगल या अंग्रेज प्रशासक या कांग्रेसी राजनेता हुआ करते थे। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विधायक का यह बयान 2008 मालेगाव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों के विशेष एनआईए अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद आया है, जिसने भगवा/हिन्दू आतंक शब्द को लेकर पिछले डेढ़ दशकों से जारी राजनीतिक बहस को एक बार फिर से गरमा दिया है। यह अजीबोगरीब है कि पत्रकारों से बात करते हुए आव्हाड ने कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। कभी कोई धर्म सनातन धर्म नाम से नहीं था। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। यही कथित सनातन धर्म था जिसने हमारे छत्रपति

शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में बाधा डाली। इसी सनातन धर्म ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम किया। इसी सनातन धर्म के अनुयायियों ने ज्योतिराव फुले की हत्या का प्रयास किया।

इन्होंने सावित्रीबाई फुले पर गोबर और गंदगी फेंकी। यही सनातन धर्म शाहू महाराज की हत्या की साजिश में शामिल था। इसने आंबेडकर को पानी पीने या स्कूल में पढ़ने की अनुमति तक नहीं दी। वहीं, आव्हाड के सनातन धर्म और सनातन समाज विरोधी बयान पर राणे और संजय निरुपम ने भी ठोककर जवाब दिया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने जितेंद्र आव्हाड के बयान पर कहा कि 'हिंदू आतंकवाद' या 'सनातनी आतंकवाद' जैसी भाषा भारत की हिंदू और संत परंपरा को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई एक परिभाषा है।

राणे की इस प्रतिक्रिया का लब्बोलुआब यह है कि हिन्दू समाज के प्रति हद से ज्यादा नकारात्मक हो चुकी कांग्रेस को देशवासियों ने सजा दी, और केंद्रीय सत्ता से बाहर कर दिया, जिससे कांग्रेसी बौखलाये हुए हैं। उसके लोग मुस्लिम वोटों को समाजवादियों से खींचने के लिए रणनीतिक गलतियां दर गलतियां करते जा रहे हैं। ऐसा करके वे लोग विपक्ष की राजनीति तो कब्जा सकते हैं, लेकिन केंद्रीय सत्ता 15 साल बाद भी उनके लिए दिल्ली दूर ही साबित होगी। वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस के तथाकथित 'इकोसिस्टम' पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सनातन धर्म को बदनाम करने और हिंदू आतंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर आमादा है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के उन हालिया बयानों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने सनातन आतंकवाद का नया जुमला गढ़ा है।

सांसद संबित पात्रा ने एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड के ताजा विवादित बयान का हवाला देते हुए कहा कि, 'आव्हाड महाराष्ट्र के नेता हैं और शरद पवार की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक बार फिर उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आपने सत्य का अपमान किया है, शिव के खिलाफ बोला है और उस भारत की सुंदरता का विरोध किया है। वह भारत जिसकी खूबसूरती सबके सम्मान में निहित है। मैं शरद पवार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह आपकी पार्टी भी यही सोचती है, स्पष्ट कीजिए।' वहीं, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए खूब सारी फर्जी कहानियां सुनाई हैं। वे यह बताना भूल गए कि अगर सनातन धर्म नहीं होता तो वे अब तक जितेंद्र नहीं जित्तुद्दीन हो जाते।

अगर सनातनी नहीं होते तो देश सऊदी अरब बन जाता। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भगवा शब्द की जगह सनातन या हिंदुत्ववादी शब्दों के उपयोग की वकालत की है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी दोषियों को बरी किए जाने के बाद चव्हाण ने सनातन संगठन की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता का हवाला देते हुए उस पर प्रतिबंध का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों के लिए 'भगवा' शब्द का प्रयोग न करके 'सनातन' या 'हिंदुत्ववादी' शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. उन्होंने अपने विचारों के समर्थन में ऐतिहासिक संदर्भ भी दिए।

चव्हाण ने कहा, 'मेरे मुख्यमंत्री काल में 'सनातन' संगठन की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता थी।' इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैंने एक गोपनीय रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी। उसी संदर्भ में मैंने 'सनातन' शब्द का उपयोग किया था, क्योंकि उस संगठन का कार्य आतंकवादी प्रवृत्ति का था। इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था।' उन्होंने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर और कॉ. गोविंद पानसरे की हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ क्या हुआ और आज तक न्याय क्यों नहीं मिला, यह गंभीर प्रश्न है।

उन्होंने सवाल उठाया और कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होनी थी, उसी समय मुंबई सीरियल ब्लास्ट और मालेगांव फैसले का आना संयोग है या साजिश? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब मालेगांव केस चल रहा था, तब जो बयान दिया था, उसका असर कोर्ट के निर्णय पर पड़ा हो, तो यह गंभीर मामला है।

चव्हाण ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, 'बीते 15 वर्षों से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन इस अवधि में जांच एजेंसियों ने न्यायोचित कार्य नहीं किया है। ये सब सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया है।' मुंबई विस्फोट और मालेगांव दोनों मामलों में सरकार को उच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए।'

चव्हाण के अनुसार, कोई भी धर्म आतंकवादी नहीं होता, लेकिन नाथूराम गोडसे की विचारधारा संघ की थी। सरदार वल्लभभाई पटेल ने एक समय संघ पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने यह भी साफ किया कि चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह ने 'भगवा आतंकवाद' शब्द का उपयोग किया था, लेकिन मैं और मेरी पार्टी उस शब्द से सहमत नहीं थे और आज भी नहीं हैं। इसलिए सनातनी आतंकवाद कहते हैं।

तल्ख हकीकत यह है कि भारत को सनातन ने नहीं, विदेशी आक्रांताओं और कांग्रेस ने बर्बाद किया। आजादी की प्राप्ति के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए तत्कालीन हिंदूवादी कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ छल किया। जबतक हिन्दू समाज इसे समझ पाया, तबतक बहुत देर हो चुकी थी। हिन्दू हित के जो कार्य 1947 में ही शुरू कर दिए जाने चाहिए थे, वो 1998-99 में प्रारंभ हुए, लेकिन उन्हें सही गति 2014 के बाद मिल पाई।

अभी भी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता इस राह में सबसे बड़ा बाधक है। यह इस्लामिक व ईसाइयत को संरक्षण देता है तो हिंदुओं को सिख, बौद्ध, जैन आदि पंथ को धर्म ठहराकर तोड़ता है। इससे हिन्दू समाज आंदोलित है। उसे योगी शासन का इंतजार है, ताकि यूपी की तरह पूरे देश का कायाकल्प संभव हो सके।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विधायक का यह बयान 2008 मालेगाव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों के विशेष एनआईए अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद आया है, जिसने भगवा/हिन्दू आतंक शब्द को लेकर पिछले डेढ़ दशकों से जारी राजनीतिक बहस को एक बार फिर से गरमा दिया है।

दहशत या हकीकत ?

हरेन्द्र शर्मा

ड्रोन की घटनाएं हकीकत हैं या अफवाह ? ये अनसुलझी पहेली जैसा है। वैसे, पिछले दो सालों से 'स्वामित्व योजना' के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण भी ड्रोनों से करवा रही है। योजना मार्च-2026 तक पूरी होनी है। करीब 3 लाख 44 हजार गांवों का सर्वेक्षण होना है।

'ड्रोन गिरोह' की अफवाहों ने शांति-व्यवस्था में खलबली मचा रखी है। विशेषकर ग्रामीणों में, जहां दहशत की स्थिति बनी हुई है। ड्रोन चारों के भय से लोग सारी-सारी रात जगे रहते हैं। प्रभावित दो-तीन राज्यों में करीब महीने भर से ड्रोन चोरों के भय से लोग इतने भयभीत हैं कि वह रातों में जाग-जाग कर अपने घरों और परिजनों की पहरेदारी कर रहे हैं। डरे हुए लोग 'ड्रोन चोरों को 'आसमानी चोर' कहने लगे हैं। आकाश में रात के वक्त सैकड़ों फीट उंचाई पर मंहराते रहस्यमय ड्रोनों से सन्नाटा इस कदर फैला है कि पेड़-पौधों के पत्तों की सरसराहट या झींगुरों की भिनभिनाहट मात्र से भी लोग डर जाते हैं। देखा जाए तो देहात क्षेत्रों में ड्रोन चोरों की अफवाहों का बाजार काफी समय से गर्म है। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड़ पर है। रात में जायजा लेने को पुलिस-प्रशासन के आला अफसर भी ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस ने जागरुकता अभियान भी छेड़ रखा है। दरअसल, अफवाह लोगों की नासमझी से ज्यादा फैल रही है। ड्रोन दिखाई पड़ने पर वह पुलिस से संपर्क करने के बजाय सोशल मीडिया पर अनापशनाप गलत सूचनाएं फैला देते हैं जिससे स्थिति और पैनिक हो रही है। हालांकि, ऐसे लोगों पर पुलिस सख्ती भी दिखा रही है।

ड्रोन की घटनाएं हकीकत हैं या अफवाह ? ये अनसुलझी पहेली जैसा है। वैसे, पिछले दो सालों से 'स्वामित्व योजना' के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण भी ड्रोनों से करवा रही है। योजना मार्च-2026 तक पूरी होनी है। करीब 3 लाख 44 हजार गांवों का सर्वेक्षण होना है। इसके पीछे सरकार का मकसद ग्रामीण संपत्ति के मालिकों को उनकी संपत्ति का मास्टर कार्ड वितरण करना है। 92 फीसदी कार्य 'ड्रोन मैपिंग' से पूरा हो चुका है जिसमें 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। सवाल ये भी उठता है क्या इस वक्त जो ड्रोन उड़ रहे हैं, वो इसी योजना का हिस्सा हैं? अभी तक कोई तथ्यात्मक सच्चाई मुकम्मल रूप से बाहर नहीं निकल पाई। जबकि, प्रथम दृष्टया प्रशासन ने ड्रोन घटनाओं को अफवाह ही माना है। ड्रोन की घटनाओं के पीछे कोई ऐसी हकीकत तो नहीं छिपी

जिसे शासन-प्रशासन और सुरक्षा महकमा सार्वजनिक ना करना चाहता हो? राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा तो कोई मसला नही? हालांकि ऐसे नाना-प्रकार के कयासों की मंड़ियां सजी हुई हैं। सच्चाई के असल नतीजों तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तकरीबन जिलों में इस समय ड्रोन लूटेरों की ही चचाएं हैं।

धीरे-धीरे ये दहशत अब अन्य राज्यों में भी फैलती जा रही है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश में भी आधुनिक चोरों से जुड़ी अजीबोगरीब अफवाहें फैल गई हैं। बिहार के सासाराम और मध्यप्रदेश के गुना जिले में भी ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। अफवाहें हैं कि चोर रात्रि में घरों का ड्रोन से सर्वेक्षण करते हैं और अगली रात धाबा बोलते हैं। एकाध घटनाएं घटी भी हैं, लेकिन उन घटनाओं से कोई हकीकत सिद्ध नहीं हुई। पुलिस-प्रशासन दोनों भी इस अनसुलझी पहेली में उलझे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर ड्रोन की घटनाओं को बेशक अफवाह बताई जा रही हों। पर, ग्रामीण मानने को राजी नहीं? वह ड्रोन चोर या आसमानी चोर ही माने बैठे हैं। बीते मात्र तीन हफ्तों में उत्तर प्रदेश में 365 और उत्तराखंड में 245 घटनाएं घटी हैं। गौरतलब है कि अफवाहों के गर्भ से निकली ड्रोन चोरी की ये घटनाएं अब हिंसा में बदलने लगी हैं। गत दिनों बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र में रात के वक्त एक खूनी घटना घटी जिसमें एक औरत का गला चाकू से रेतकर उसे जहर का इंजेक्शन देने का प्रयास हुआ। गनीमत ये रही कि उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। सुबह पुलिस ने छानबीन कर आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो पता चला महिला पर हमला ड्रोन चोरों ने नहीं, बल्कि पड़ोसी ने किया जिनसे उनका पुराना जमीन विवाद चल रहा है। चोर समझकर अंधेरे में चलने वाले राहगीरों के साथ मारपीट की घटनाएं भी बढ़ी हैं। शराबियों की तो सामात ही आई हुई है। बिलावजह हादसे का शिकार न हो जाएं, इसलिए रात्रि पाली में काम करने वाले कर्मचारी भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसे भी घटनाएं खूब सामने आ रही हैं, जहां ड्रोन चोरों की आड़ में लोग अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। दशहत और अफवाहें इस कदर देहतों में व्याप्त है कि आसमान में चमकती रौशनी को भी ड्रोन समझ कर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।

दहशत के चलते ग्रामीण पूरी-पूरी रात अपनी छतों पर बल्ब और टॉर्च जलाकर बैठे रहते हैं। जुगनुओं की रौशनी से भी चिल्ला पुकार मचने लगता है। सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोरों ने कुछ ज्यादा माहौल बिगाड़ा हुआ है। माहौल जैसे-जैसे बिगड़ना तेज हुआ, तो राज्य सरकार का ध्यान एकाएक उस ओर गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल आपातकाल बैठक बुलाई। हालांकि, उससे पहले ही अधिकारियों ने शासन को ड्रोन्स के संबंध में कुछ उत्पाती लोग उन्माद फैलाने की फिराक में होना दर्शा दिया था। शासन ने निर्णय लिया है कि ड्रोन के जरिए डर पैदा करने या गलत सूचना फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाही की जाएगी। लेकिन, शासकीय चेतावनी के बाद भी ड्रोन का उड़ना लगातार जारी है। दो दिन पहले भी मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में एक और उच्च-स्तरीय कानून-व्यवस्था को दुरूस्त करने को लेकर बैठक हुई, जिसमें बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाही का आदेश पारित हुआ। जिसके उलघन में कुछ यूटयूबर और कैटरिंग वाले पकड़े गए। फिलहाल, पुलिस की पूछताछ में उनकी ड्रोन हरकतों में संलिप्ता नहीं मिली।

गौतललब है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में समय-समय पर किस्म-किस्म के चोर गिरोहों से अफवाहें फैलती रही हैं। चोटी कटवा, कच्छा-बनिया गिरोह, बाबा गिरोह, तलवारधारी गिरोह जैसे तमाम चोरों के गिरोह की सूचनाएं पुर्व में सुनने को मिलती रहीं। मौजूदा ड्रोन से जुड़ी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड और यूपी सरकार ने बकायदा पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जहां रात्रि के वक्त रोजाना सैकड़ों कॉल्स ड्रोन देखे जाने के संबंध में आ रही हैं। 7900 कॉल्स को पुलिस ने अभी तक रिकॉर्ड किया है जिसकी सत्यता पूरी तरह उन्माद से प्रेरित ही पाई गई। ड्रोन देखे जाने की सूचनाएं ज्यादातर अफवाहें ही साबित हो रही हैं जिनका किसी गिरोह से कोई संबंध फिलहाल दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता? प्रशासन को 'ड्रोन लुटेरों' से फैली अफवाहों पर तुरंत अंकुश लगाना होगा, नहीं तो ग्रामीण ड्रोन गिरोह के सदस्यों के शक में बेकसूर लोगों को निशाना बनाते रहेंगे। बरेली में पिछले शनिवार को सबसे दर्दनाक घटना हुई, जहां मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को 'ड्रोन गिरोह' का सदस्य समझकर लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला।

अमेरिकी दादागिरी पर मोदी की ललकार

हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा को प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल अनुचित और एकतरफा करार दिया, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब वैश्विक मंच पर दबाव में आने वाला नहीं है।

भारत किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा

देश के अग्रणी कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि-क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ललकारभरे शब्दों में अमेरिकी टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा, भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का द्योतक है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ को भारत ने अनुचित एवं दुर्भावनापूर्ण बताया है। भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने के दबाव कभी नहीं आयेगा क्योंकि भारत के लिये यह एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। इस समारोह में मोदी ने जो शब्द कहे, वे केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि नये भारत, सशक्त भारत की एक स्पष्ट नीति का घोषणा पत्र है, भारत की नई कृषि रणनीति, आत्मनिर्भरता की भावना और अमेरिकी टैरिफ की दादागिरी को खुली चुनौती है। भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी टैरिफ पर पहली

ललित कुमार

बार प्रतिक्रिया दी, और अमेरिका या डॉनल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ भारत कभी समझौता नहीं करेगा। भारत ने इससे पहले ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन बताया था। यह विडम्बनापूर्ण एवं विसंगतिपूर्ण है कि ट्रंप बातें रूस की कर रहे हैं, लेकिन यह समझना आसान है कि उनकी निराशा के मूल में भारत के साथ अटकी कृषि ट्रेड डील भी है। वह चाहते हैं कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों और डेयरी प्रॉडक्ट्स के लिए अपना बाजार खोले। लेकिन देश की बड़ी आबादी खेती पर आश्रित है और किसान आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं। इसलिये वे सब्सिडाइज्ड अमेरिकी प्रॉडक्ट्स से होड़ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के जरिये भारत का यही पक्ष एवं किसानों की चिन्ता को रखा है। लेकिन ट्रंप इस चिंता को शायद ही समझें, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अपनी हर नाकामी का ठीकरा फोड़ने के लिए उन्हें कोई देश चाहिए। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का दबाव व यूक्रेन युद्ध न रुकवा पाने की हताशा ट्रंप के फैसलों में बौखलाहट के रूप में झलक रही है। पहले उन्होंने चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वहां से 'रेयर अर्थ मिनरल्स' के रूप में झटका लगा, तो भारत और रूस से अपनी बात मनवाना चाहते हैं।

हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा को प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल अनुचित और एकतरफा करार दिया, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब वैश्विक मंच पर दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका की यह टैरिफ नीति, डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों के विरुद्ध और विकासशील देशों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का प्रतीक है। भारत पर विशेषकर चावल, गेहूं, दलहन, और मसालों के निर्यात में टैरिफ

लगाना सीधे-सीधे भारतीय किसानों की आय पर प्रहार है। ऐसे समय में जब भारत कृषि निर्यात को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहा है, अमेरिका की यह नीति दादागिरीपूर्ण व्यापारवाद का उदाहरण है। भले ही ट्रंप की टैरिफ पैंतरों ने दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी हो, लेकिन भारत ऐसी चुनौतियों के सामने झुकने वाला नहीं है।

भारत अब केवल अमेरिका या यूरोप पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अफ्रीका, खाड़ी देशों, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय कृषि व्यापार समझौते तेजी से किए जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादन का प्रोत्साहन, 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' के तहत कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बल दिया जा रहा है, जिससे निर्यात योग्य उत्पादों का मूल्यवर्धन हो सके। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तकनीक के माध्यम से किसानों को वैश्विक बाजार की जानकारी, टैरिफ डाटा और निर्यात संभावनाओं से जोड़कर किसानों की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। भारत टैरिफ के जवाब में टैरिफ की राह पर बढ़ते हुए यदि आवश्यकता पड़ी, तो प्रतिस्पर्धी टैरिफ नीति के तहत अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने से नहीं हिचकिचाएगा। भारत डब्ल्यूटीओ और जी20 आदि मंचों पर आक्रामक कूटनीति का सहारे लेकर अब विकासशील देशों की आवाज बनकर, अमेरिका की एकतरफा नीतियों का जवाब दे रहा है।

देश को धीरे-धीरे समझ आने लगा है कि भारतीय कृषि व डेरी क्षेत्र में अमेरिकी उत्पाद खपाने के लिये ही डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ आंतक फैला रहे हैं। यही वजह है कि पहले संयम दिखाने के बाद भारत ने निरंकुश ट्रंप सरकार को चेता दिया है कि भारतीय किसानों व दुग्ध उत्पादकों के हितों की बलि नहीं दी जा सकती। हमारे लिये यह देश की एक बड़ी कृषि व डेरी उद्योग से जुड़ी आबादी के जीवन-यापन का भी प्रश्न है। बहरहाल, यह तय हो गया है कि भारत वाशिंगटन के उन मंसूबों पर पानी फेरने के लिये खड़ा हो गया है, जिनके तहत अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और इथेनॉल जैसे उत्पादों से कम टैरिफ के साथ भारत के बाजार को पाटना चाहता है। निस्संदेह, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले तीन प्रमुख क्षेत्रों कृषि, डेरी फार्मिंग और मत्स्य पालन से जुड़े करोड़ों लोगों की अजीविका की रक्षा करने के लिये प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता सराहनीय है।

एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आते ही भारतीय कृषि का वह स्वर्णिम अध्याय सामने आता है, जब देश अन्न के लिए विदेशों पर आश्रित था और अकाल एक आम त्रासदी हुआ करती थी। 1960 के दशक में स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी), उर्वरकों और सिंचाई तकनीक का ऐसा संगम किया जिसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई हरित क्रांति ने न केवल खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि भारत की कृषि पहचान को वैश्विक पटल पर स्थापित किया। उनकी रिपोर्टें, विशेष रूप से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, आज भी किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें बाजार से न्याय दिलाने की कुंजी मानी जाती हैं। उन्होंने 'किसान केंद्रित कृषि नीति' का विचार दिया, जिसमें किसानों को केवल उत्पादनकर्ता नहीं, बल्कि राष्ट्रनिमार्ता माना गया। मोदी इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए न केवल किसानों के हितों के साध रहे हैं, बल्कि भारतीय कृषि को नये भारत का आधार बनाने के लिये संकल्पबद्ध है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि भारतीय राजनीति में किसान उत्पादक व उपभोक्ता से इतर बड़ा राजनीतिक घटक भी है। ऐसे में जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी कृषक समुदाय को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी का जोर अब 'अन्नदाता को ऊजार्दाता' बनाने पर है। इसके लिए कृषि के तीन प्रमुख मोर्चों पर काम हो रहा है- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनाना। कृषि निर्यात को 50 बिलियन डॉलर से ऊपर ले जाना। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को चरणबद्ध लागू करना, जिससे किसानों को लागत से 50 प्रतिशत अधिक लाभ मिल सके। आज जब हम एम.एस. स्वामीनाथन की वैज्ञानिक दृष्टि को याद करते हैं, तो स्पष्ट होता है कि उनकी सोच सिर्फ उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि किसान को सशक्त करने, आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक ताकतों के सामने टिके रहने योग्य बनाने की थी। मोदी की यह नई नीति उसी दर्शन की राजनीतिक अभिव्यक्ति है।

सही मायनों में भारतीय कृषि में उन आमूल-चूल परिवर्तनों की आवश्यकता है जो न केवल किसान की आय बढ़ाएं बल्कि कृषि उत्पादों को विश्व बाजार की चुनौतियों से मुकाबला करने में भी सक्षम बनायें। एक सौ चालीस करोड़ आबादी वाला देश भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इस आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम हर हालात में मेहनतकश अन्नदाता को पूरे दिल से समर्थन दें। भारत अब 'झुककर व्यापार' नहीं करेगा, बल्कि 'सम्मान के साथ साझेदारी' करेगा। अमेरिका जैसे देशों को यह समझना होगा कि भारतीय किसान अब केवल हल चलाने वाला नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार का खिलाड़ी है। और जब उसके पीछे स्वामीनाथन की विरासत और मोदी की नेतृत्वशक्ति हो, तो कोई भी टैरिफ, कोई भी दबाव, भारत की कृषि शक्ति को झुका नहीं सकता।

टैरिफ आर्थिक युद्ध नहीं, आत्मनिर्भर शांति का रास्ता बने

डोनाल्ड ट्रंप की नीति अक्सर 'दबाव डालो और झुकावो' पर आधारित रही है। चीन, यूरोप, मैक्सिको के साथ भी ट्रंप की व्यापार नीति टकरावपूर्ण रही है। लेकिन भारत, ऐतिहासिक रूप से संतुलन साधने वाली कूटनीति में विश्वास करता रहा है।

मनोज शर्मा

जब किसी वैश्विक ताकत के शिखर पर बैठा नेता 'व्यापार' को भी 'सौदेबाजी' और 'दबाव नीति' का औजार बना ले, तब यह न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर देता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधारभूत सिद्धांतों को भी चुनौती देता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाकर ऐसा ही एक आर्थिक आघात पहुँचाया है। इस टैरिफ का लक्ष्य स्पष्ट है, भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को बाधित करना और अमेरिकी वर्चस्व की पुनः स्थापना करना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य एवं भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 'ट्रंपीय' दादागिरी, एवं टैरिफ का तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव कितना क्या असर दिखायेगी, यह भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन इस सन्दर्भ में भारत सरकार की दृढ़ता सराहनीय है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, दोनों का द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 190 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। ट्रंप और मोदी ने इस आंकड़े को दोगुना से भी ज्यादा 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उस लक्ष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। ऐसे में, भारतीय कंपनियों को बहुत संभलकर अपने लिए नए बाजार खोजने व बढ़ाने चाहिए।

भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने भारत को उत्पादन और नवाचार का नया केंद्र बनाया है। भारत का टेक्सटाइल, स्टील, ऑटो पार्ट्स और आईटी सेवा क्षेत्र वैश्विक बाजार में निरंतर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा टैरिफ थोपना भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा से उपजे भय का संकेत है। लेकिन यह निर्णय केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। ट्रंप प्रशासन हमेशा से ही व्यापार संतुलन के मुद्दे को राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देखता रहा है। 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति का मुख्य हथियार रहा है, दूसरों को पीछे धकेलकर अमेरिका को आगे लाना। यह एकतरफा सोच व्यापार के मूल्यों और साझेदारी की भावना को कमजोर करती है। व्यापार समझौते पर 1 अगस्त की समय सीमा तक दोनों देशों के बीच जारी बातचीत किसी नतीजे पर न पहुंचने का बड़ा कारण भारत का अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होना रहा है। उसे आगे भी तैयार नहीं होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि भारत अमेरिका से ऐसा व्यापार समझौता कर ले, जो केवल उसके हित में हो। इस तरह के समझौते तो तभी हो पाते हैं, जब दोनों पक्षों के हित सधते हैं। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अडिग रहना चाहिए और यह स्पष्ट करने में संकोच भी नहीं करना चाहिए कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुचित दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। भारत को ट्रंप के मनमाने फैसलों से डरने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं, क्योंकि वे अपने फैसलों से पीछे हटने और उन्हें पलटने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस रवैये के कारण उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत भी हो रही है। उन्हें यह समझ आ जाए तो अच्छा कि आज का भारत पहले वाला

भारत नहीं है और अमेरिका का भी प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा।

डोनाल्ड ट्रंप की नीति अक्सर 'दबाव डालो और झुकावो' पर आधारित रही है। चीन, यूरोप, मैक्सिको के साथ भी ट्रंप की व्यापार नीति टकरावपूर्ण रही है। लेकिन भारत, ऐतिहासिक रूप से संतुलन साधने वाली कूटनीति में विश्वास करता रहा है। भारत ने कई बार वार्ता के माध्यम से समझौते की दिशा में पहल की, लेकिन ट्रंप की आक्रामक नीति और 'डीलमेकिंग' की व्यक्तिगत शैली ने किसी संतुलन को बनने नहीं दिया। भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत टैरिफ न केवल आर्थिक रूप से अनुचित है, बल्कि यह उभरते राष्ट्रों के आत्मनिर्भर बनने के अधिकार का भी हनन है। यह नव-उपनिवेशवाद का नया रूप है, जहँ आर्थिक हथियारों से शक्तिशाली राष्ट्र, विकासशील देशों को नियंत्रित करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने और जुमार्ना लगाने की जो घोषणा की, वह उनकी दबाव की राजनीति का ही हिस्सा है। इस राजनीति की पोल खुल चुकी है। अच्छा होगा कि इसे देश के विपक्षी दल भी समझें। इसलिए और भी समझें कि संसद में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि सैन्य कार्रवाई को स्थगित किए जाने के सिलसिले में विश्व के किसी भी नेता की कहीं कोई भूमिका नहीं। स्पष्ट है कि भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई को कथित तौर पर रोकने का ट्रंप का दावा फर्जी है। वास्तव में इसी कारण वे अपने इस थोथे दावे को बार-बार दोहरा रहे हैं।

आज का भारत न केवल एक विशाल बाजार है, बल्कि एक नवाचारशील शक्ति भी है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, और विविधता से समृद्ध उत्पादन क्षमता भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रही है। भारत अब ह्वनिर्भरताह्व की नीति से निकलकर ह्वआत्मनिर्भरताह्व की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव सीमित और अस्थायी होगा, लेकिन भारत की आर्थिक विकास यात्रा दीर्घकालिक और दृढ़ है। भारत के लिए यह चुनौती अवसर में बदलने का समय है, नए बाजारों की तलाश, घरेलू उत्पादन को और सशक्त बनाना, और वैश्विक साझेदारियों को नए रूप में ढालना। ट्रंप की दादागिरी भारत को झुका नहीं सकती। बल्कि यह भारत को और मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे सकती है। यह समय है जब भारत को अपने उत्पादन, नवाचार, निर्यात और कूटनीति को और धार देने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि शक्ति का उत्तर शक्ति से नहीं, दूरदृष्टि और नीति से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का टैरिफ एक चुनौती है, लेकिन भारत की आत्मा में संघर्ष से जीतने का इतिहास है। हमने हर संकट को अवसर में बदला है, और इस बार भी हम यही करेंगे, न केवल अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए भी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्थिक चिंतन मूलतः 'आत्मनिर्भर भारत', 'विकास के साथ विश्वास', और 'समान साझेदारी' के सिद्धांतों पर आधारित रहा है। वे वैश्विक मंच पर भारत को एक समानाधिकार संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि किसी बड़े राष्ट्र की कृपा पर चलने वाली व्यवस्था के रूप में। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ का प्रहार करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की सोच विरोध नहीं, विकल्प पर आधारित होती है। वे इस तरह के दबावों को एक नई दिशा में सोचने और घरेलू उत्पादन एवं वैश्विक विविधीकरण का अवसर मानते हैं। टैरिफ वार के उत्तर में मोदी की प्रतिक्रिया सकारात्मक ही होती हुई दिख रही है, वे ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों जैसे स्टील, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल को सरकारी सब्सिडी, टैक्स रियायत और तकनीकी समर्थन के जरिए बल दे सकते हैं। अमेरिका के अतिरिक्त यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में भारत अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए इस टैरिफ से उत्पन्न संकट को संतुलित कर सकता है।

ट्रंप भारत को अपना मित्र मानते हैं। लेकिन यह कैसी मित्रता है, जिसमें ट्रंप को भारत के गरीबों, किसानों, मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन मोदी की विदेश नीति में भी 'अमेरिका के साथ मित्रता' है, लेकिन 'आत्मगौरव की कीमत पर नहीं'। वे संवाद और दृढ़ता-दोनों का प्रयोग करते हैं। दबाव की राजनीति से न तो भारत झुकेगा, न रुकेगा। ट्रंप का टैरिफ हो या कोई और वैश्विक चुनौती, मोदी का भारत हर संकट में अवसर खोजता है। मोदी की आर्थिक दृष्टि एवं नीतियां किसी बाहरी राष्ट्र के मनोनुकूल नहीं, बल्कि भारत की आवश्यकताओं, संभावनाओं और स्वाभिमान के अनुरूप गढ़ी गई है। जब वैश्विक महाशक्तियां टैरिफ के हथियार से डराने लगें, तो समझो कि भारत की प्रतिस्पर्धा ने उन्हें असहज कर दिया है। मोदी इसे चुनौती नहीं, पहचान मानते हैं। मोदी कहते हैं-'लोकल को ग्लोबल बनाओ', और यही उनका उत्तर है हर टैरिफ, हर दबाव, हर चुनौती को। मोदी की अर्थनीति उद्यमशीलता को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ती है। उनका आर्थिक चिंतन 'केवल विकास' नहीं, बल्कि स्वराज्य आधारित समावेशी आर्थिक स्वतंत्रता है। ट्रंप के टैरिफ की चुनौती को वे उसी तरह लेते हैं जैसे उन्होंने कोविड या ग्लोबल मंदी की ली थी-साहस, दूरदर्शिता और आत्मनिर्भरता के साथ।

क्या भारत के लिए खतरा बन सकती है ट्रंप-मुनीर की नई जोड़ी ?

सचिन तोमर

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब जनरल मुनीर ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिरयानी का स्वाद चखा और फिर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम नामित किया, भारत तभी से इस मित्रता से प्रति सतर्क हो गया है।

ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। विगत दिनों भारतीय वायुसेना प्रमुख का वक्तव्य आया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पांच फाइटर जेट लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। थलसेना प्रमुख ने भी जल्द एक युद्ध होने और आगामी युद्ध दो देशों के बीच नही अपितु कई मोर्चों पर होगा कहकर हड़कंप मचा दिया है। कर्नाटक की रैली में कांग्रेस नेताओं के समक्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उल्लेख कर दिया जिससे पाकिस्तान का तिलमिला जाना स्वाभाविक ही है।

उधर आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से प्यार हो गया है और वह दो बार वाशिंगटन यात्रा कर आया है इससे जनरल मुनीर का दिलो दिमाग खराब होना तय है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब जनरल मुनीर ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिरयानी का स्वाद चखा और फिर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम नामित किया, भारत तभी से इस मित्रता से प्रति सतर्क हो गया है।

जून 2025 के बाद असीम मुनीर दो महीने में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा कर आए हैं। मुनीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिला के विदाई समारोह में भाग लिया और नये कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को बधाई दी। इसमें महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अमेरिका की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें वह पाकिस्तान को ही आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र मान

रहा है वह भी तब अमेरिका का सबसे बड़ा गुनाहगार पाकिस्तान में ही पाया गया था और आज भी वहां पर 126 प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के नेता खुलेआम घूम रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे संगठनों को आतंकी संगठन घोषित करते हुए उन्हें प्रतिबंधित किया है, उससे मुनीर की बांछें खिलना तय है।

अमेरिका में हो रही पाकिस्तानी हितों की सुरक्षा से उत्साहित पाक सेना प्रमुख ने अमेरिकी धरती से भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दे डाली और उसके बाद अन्य पाक नेताओ के भी वैसे ही बयां आने लगे आने लग गये। इन नेताओं में पूर्व विदेशमंत्री बिलावल भुट्टो व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हैं। भारत-अमेरिका संबंधों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिकी धरती से भारत को परमाणु धमकी मिली है। रक्षा विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि मुनीर को यह ताकत अमेरिकी नीतियों के कारण ही मिल रही है। इसके पीछे एक बात यह भी हो सकती है कि अमेरिका भारत पर लगतार टैरिफ पर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहा है किंतु भारत पर अमेरिकी धमकियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। भारत किसी दबाव के आगे बिना झुके अपने विकास के संकल्पों के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार यह बयान दे रहे हैं कि उनकी वजह से ही भारत-पाकिस्तान के मध्य संघर्ष विराम हुआ किंतु भारत उनकी इस थ्योरी को बार- बार खारिज कर रहा है कि भारत -पाक के मध्य संघर्ष विराम अमेरिका की मध्यस्थता के कारण हुआ। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति को बुरी लग रही है और वे पाकिस्तान से गलबहियां करते दिख रहे हैं।

मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। मुनीर की बातो में परमाणु शक्ति संपन्न होने का अहंकार स्पष्ट दिख रहा है। उसने कहा कि जब हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। इसमे सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि एक तरफ अमेरिका और इजरायल ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देने के लिए उस पर हमला कर रहे हैं और ईरान को तबाह करने के लिए तैयार हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान उसकी धरती पर ही आधी दुनिया को मिटाने की बात कह रहा है। मुनीर के बयान ने दक्षिण एशिया और वैश्विक मंच पर तनाव बढ़ा दिया है। मुनीर सिंधु जल संधि को लेकर भी धमकी दे रहा है कि अगर भारत बांध बनाएगा उसे पाकिस्तान 10 मिसाइलों से नष्ट कर देगा। मुनीर को ऐसा क्यों लगता है कि भारत के पास मिसाइलें हैं ही नहीं या पाक से मिसाइलें आने पर भारत हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा ?

भारत के लिए परमाणु धमकी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है और भारत कई बार स्पष्ट कर चुका है कि परमाणु ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलने वाली है। भारत स्वयं एक जिम्मेदार और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। पाकिस्तान को यह भी समझना होगा कि उनके परमाणु हथियार तो भारत पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिए जाएंगे किन्तु जब भारत पलटवार करेगा तब पाकिस्तान का एक कोना भी नहीं बचेगा।

पाक सेना प्रमुख जनरल मुनीर के बयान के बाद अमेरिका से ही उसके खिलाफ कड़ी आवाज उठने लगी है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाक सेना प्रमुख मुनीर की ओर से अमेरिकी धरती से दी गई धमकी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर सेना की वर्दी में आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। रूबिन ने अमेरिकी प्रशासन को सुझाव दिया है कि जनरल मुनीर को अवांछित व्यक्ति घोषित कर उनके अमेरिका वीजा पर तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

अमेरिका के प्रश्रय में पाकिस्तान ह्लएक दुष्ट देशह्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। पाकिस्तान एक तरफ आतंकवाद से लड़ने का दावा कर रहा है वहीं दूसरी तरफ वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामित आतंकी समूहों को समर्थन व संरक्षण दे रहा है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही तालिबान और अलकायदा को पैदा किया। पाकिस्तान की सेना ने शीततयुद्ध के दौर में ही अमेरिका से पैसा और राजनयिक संरक्षण हासिल किया है। उसने इन सबका प्रयोग पाकिस्तान के नागरिकों की भलाई करने के लिए नहीं अपितु अपने संकीर्ण और विनाशक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया। पाकिस्तान में ही लश्कर-ए-तैयबा व जैश जैसे संगठन फल फूल रहे हैं।

पाक सेना प्रमुख मुनीर एक खतरनाक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मुनीर ही है और उस मुनीर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति का बिरयानी खाना भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है किन्तु भारत अत्यंत सवाधनी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस समय इतनी नीचता पर उतर आया है कि उसने नापाक हरकत करते हुए इस्लामाबाद में भारतीय राजनायिकों के घरों में मिनरल वाटर, गैस और अखबार की आपूर्ति रोक दी है। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है और राजधानी दिल्ली स्थित पाक दूतावास में अखबार देना बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान एक निकृष्ट शत्रु राष्ट्र है और वह उसी भाषा में समझाने लायक है।

सत्य की विजय और भ्रमित विमर्श का अंत

एन के शर्मा

29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए भीषण बम विस्फोट ने न केवल छह निर्दोष लोगों की जान ले ली और 95 से अधिक नागरिकों को घायल कर दिया, बल्कि भारत की सामाजिक चेतना और राजनीतिक विमर्श में भी गहरा ध्वंस पैदा क र दिया। यह विस्फोट मस्जिद के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल में लगाए गए बम से हुआ था, जब नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर निकल रहे थे। घटना की भयावहता से पूरा देश सन्न रह गया।

मालेगांव, जो पहले से ही धार्मिक रूप से संवेदनशील नगर माना जाता रहा है, इस त्रासदी के बाद एक राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। प्रारंभिक जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने की, जिसने कुछ ही समय में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य पांच व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया। इन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए, जिन्हें एक विशिष्ट धार्मिक पहचान से जोड़कर प्रचारित किया गया।

विचारधारा से जुड़ा विमर्श और भ्रम का विस्तार

विस्फोट के तुरंत बाद देश के कुछ राजनीतिक दलों और समाचार माध्यमों ने एक ऐसा विमर्श स्थापित करना शुरू किया जिसमें आतंकवाद को एक विशेष रंग से जोड़ने का प्रयास किया गया। तथाकथित 'रंग-आधारित आतंकवाद' जैसे शब्द चलन में आए, और राष्ट्र को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि आतंकवाद अब किसी एक पंथ या समूह तक सीमित नहीं रहा। यदि यह विमर्श केवल न्यायसंगत तथ्यों के आधार पर चलता, तो इसकी प्रासंगिकता स्वीकार की जा सकती थी। परंतु, जिस प्रकार बिना ठोस प्रमाणों के, विचारधारा विशेष से जुड़े लोगों को अभियुक्त घोषित किया गया, उससे न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता पर

न्यायपालिका का निर्णय और सामाजिक प्रभाव

इस निर्णय का महत्व केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और वैचारिक विमर्श का निर्णायक क्षण भी है। वर्षों तक जिस झूठे विमर्श को प्रचारित किया गया, वह अब न्यायपालिका की कसौटी पर असत्य सिद्ध हुआ। यह निर्णय पुनः यह स्थापित करता है कि आतंकवाद न किसी धर्म का होता है, न किसी रंग का। आतंक की पहचान विचारधारा से नहीं, कृत्य से होती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आरोपितों को राहत मिलने के बावजूद, पीड़ितों के लिए यह निर्णय पूर्ण न्याय का रूप नहीं ले सका। सही अपराधी अभी भी दंड से दूर हैं।

प्रश्नचिह्न लगने लगे। बिना निष्कर्ष तक पहुंचे मीडिया में बहसें चलीं, और समाज को भ्रमित करने वाला एक धारावाहिक प्रस्तुत कर दिया गया।

केस की दिशा और वर्षों की प्रतीक्षा

2011 में यह केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपा गया। जांच में कई तकनीकी खामियाँ सामने आईं। अनेक गवाहों ने अपने बयान बदले, और कई महत्वपूर्ण सबूत न्यायिक दृष्टि से असंगत पाए गए। अभियोजन पक्ष केस को प्रमाणों के आधार पर सशक्त रूप से सिद्ध नहीं कर सका।

अंततः 31 जुलाई 2025 को विशेष एनआईए न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि अभियोजन पक्ष सातों आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं कर सका। अतः साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित सभी सातों व्यक्तियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। जिन धाराओं में उन्हें गिरफ़्तार किया गया था–जैसे गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं–वे सब प्रमाणों के अभाव में न्यायपालिका के समक्ष टिक नहीं पाईं।

सामाजिक संतुलन के लिए चेतना आवश्यक

मालेगांव केस का यह परिणाम भारतीय समाज के लिए आत्मचिंतन का अवसर है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि जांच एजेंसियों को किसी प्रकार के राजनैतिक या वैचारिक दबाव से दूर रहकर केवल प्रमाण और निष्पक्षता के आधार पर कार्य करना चाहिए। मीडिया, जो जनता का मार्गदर्शन करने वाला माध्यम है, उसे विशेष रूप से यह समझना होगा कि किसी भी केस की प्रारंभिक रिपोर्टिंग निर्णायक न हो,क्योंकि न्याय का अंतिम निर्धारण केवल न्यायपालिका ही कर सकती है। इस केस ने यह भी सिद्ध कर दिया कि किसी समूह, विचारधारा या पंथ को केवल संदेह के आधार पर दोषी ठहराना समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर सकता है। किसी भी सभ्य राष्ट्र में दोष की पुष्टि केवल तथ्यों और प्रमाणों से होनी चाहिए, न कि पूर्वाग्रहों से।

न्याय और संतुलन की पुनर्स्थापना

मालेगांव विस्फोट से जुड़ा यह निर्णय भारत की न्यायिक प्रक्रिया की स्थिरता, विवेक और धैर्य का उदाहरण है। यह निर्णय दशार्ता है कि सत्य को दबाया तो जा सकता है, पर पराजित नहीं किया जा सकता। आगे का मार्ग यही है कि ऐसी घटनाओं की जांच सशक्त, समयबद्ध और तकनीकी रूप से सक्षम हो। साथ ही, समाज को भी यह सजग दृष्टिकोण अपनाना होगा कि वह किसी प्रचार या अफवाह के बहकावे में न आए।

देश की सामाजिक एकता तभी सुरक्षित रह सकती है, जब दोष का निर्धारण विचारधारा नहीं, प्रमाण से हो; और जब न्याय का उद्देश्य केवल सजा नहीं, बल्कि सच्चाई की स्थापना है।

विवेक, सत्य और न्याय की पुनर्प्रतिष्ठा मालेगांव केस के संबंध में विशेष न्यायपालिका का यह निर्णय केवल आरोपमुक्ति का निर्णय नहीं है, यह एक युगांतकारी मोड़ है–जहाँ लंबे समय तक स्थापित किया गया झूठ परास्त हुआ और सत्य विजयी हुआ। यह निर्णय हमें याद दिलाता है कि भारत का लोकतंत्र केवल मतपत्र से नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय से सशक्त होता है। अब हम सभी का दायित्व है कि हम इस अवसर का उपयोग सामाजिक विश्वास को सशक्त करने में करें,जिससे भविष्य में न कोई निरपराध झूठे आरोपों का शिकार हो और न किसी पीड़ित को न्याय के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़े।

छांगुर बाबा: भिखारी से पीर बनने तक का सफर

छांगुर गैंग के सरगना छांगुर, जिसका असली नाम जमालुद्दीन है, को अंततः पकड़ लिया गया है। आगे बढने से पहले जमालुद्दीन के बारे में थोड़ा जान लेना बेहतर होगा। वह और उसके दोनों भाई सडकों पर भीख मांगने का काम करते थे। जमालुद्दीन ने भीख मांगने का काम बलरामपुर और उसके आसपास के गांवों में सीमित न रहकर मुंबई में जाकर करने का फैसला कर लिया। मुंबई में उसका यह धंधा चला या नहीं, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन वहां उसने कुछ लोगों के साथ मिल कर अपने आप को पीर घोषित कर दिया और अपना पीरनुमा नाम छांगुर बाबा रख लिया। यह रहस्य अभी भी बना हुआ है कि उसने स्वयं अपने आप को पीर बनाने का फैसला किया या किसी विदेशी षड्यंत्रकारी ने उसे पीर बनाने का फैसला किया? लेकिन इतना निश्चित है कि पीर का धंधा जब चल निकला तो

अरुण शर्मा

उसने अपना मुख्यालय भारत-नेपाल सीमा पर बनाने का निर्णय किया। अब तक उसके विदेशी सहायकों ने उसका प्रभाव व आतंक इतना फैला दिया था कि उसने बलरामपुर में जमीन खरीद कर मुख्यालय बनाने की बजाय सरकारी जमीन पर ही कब्जा करना बेहतर समझा।

जाहिर है यह काम सरकारी अधिकारियों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता था। अंततः छांगुर को नेपाल की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से ही गिरफ्तार किया गया है। छांगुर उस प्रकार का सरगना नहीं था जो बरसों से पुलिस से बच कर भाग रहा हो और राज्य की पुलिस उसके लिए जगह जगह दबिश दे रही हो। इसके विपरीत वह अपने आलीशान महल, जिसे किला भी कहा जा सकता है, में सम्मान सहित रहता था। उसको पकडने के लिए दबिश नहीं दी जा रही थी, बल्कि सरकारी अधिकारी भी उसकी नजर-ए-इनायत के लिए उसके आगे नतमस्तक होते थे। लेकिन कुछ सरकारी अधिकारी उसकी करतूतों को जानते थे और उसकी सहायता करते थे। इसका अर्थ है कि वे सरकारी अधिकारी भी उसकी उन योजनाओं से सहमत थे जिनको वह क्रियान्वित कर रहा था।

वे योजनाएं क्या थीं, इसका अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। बड़ी योजना तो मतांतरण की थी। यानी भारतीय अपने परंपरागत सनातन रीति-रिवाजों, आस्थाओं, प्रतीकों को त्याग कर अरब मूल के इस्लाम मजहब में शामिल हो जाएं। इस

बड़ी योजना को पूरा करने के लिए वह अनेक सहायक योजनाएं चलाता था। यह भी कहा जा सकता है कि इस बड़ी योजना को पूरा करने के लिए उसकी पद्धति क्या थी? अब इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मतांतरण के इस खेल में वह भारतीय लड़कियों को ही ज्यादातर निशाना बनाता था। लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने मुसलमान समाज के अनेक लडके पाल रखे थे या तनख्वाह पर भरती किए हुए थे। योजना क्योंकि गुप्त रखी गई थी, इसलिए इन मुसलमान लडकों के भी अरबी नाम बदल कर भारतीय/हिंदू नाम कर दिए जाते थे।

छांगुर का यह गिरोह लव जिहाद के सहारे लड़कियों को, छांगुर की चमत्कारी शक्तियों का झूठा प्रचार कर अन्य भोले भाले लोगों को घेरकर उसके अड्डे पर लेकर आने का काम करता था। जो लड़कियां इनके लव जिहाद के जाल में फंस जाती थीं, उनसे बलात्कार कर उसके वीडियो बना कर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। उनसे उनका मजहब बदलवा कर उनसे निकाह किया जाता था। निकाह के लिए मौलवियों की जरूरत होती थी। जाहिर है छांगुर के इस गिरोह में एक अलग से मौलवी ब्रिगेड भी रही होगी। कई लड़कियों को मतांतरण के बाद देह व्यापार में लगा दिया जाता था। लेकिन इतना स्पष्ट है कि फंसाने के इस षड्यंत्र में सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जाता था।

लेकिन लड़कियों का मजहब बदल कर उनसे निकाह कर लिया जाता था। छांगुर की योजना यहीं खत्म नहीं होती थी। यह तो मात्र शुरूआत होती थी। इन बदकिस्मत लड़कियों को आगे और भारतीय लड़कियों को किसी न किसी तरह घेर-घार कर छांगुर के अड्डे पर लाने के लिए विवश किया जाता था। इन लड़कियों को अरबी शेखों को बेच दिया जाता था। इनको आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने के लिए तैयार किया जाता था। इस मामले की परतें तब खुलने लगीं जब मार्च 2025 में आगरा से दो लड़कियां लापता हो गईं। पुलिस छानबीन करते करते कोलकाता तक पहुंच गई। पता चला कि कोलकाता में ही दोनों लड़कियों को किसी मुस्लिम बस्ती में छिपा कर रखा गया था। पुलिस जब दोनों लड़कियों को छुड़ाने में कामयाब हुई तो उन लड़कियों ने जो खुलासे किए, तो पुलिस की छानबीन से एक के बाद एक रहस्य खुलने लगे। लेकिन जाहिर है कि इतना बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए बहुत पैसा

चाहिए। आखिर छांगुर के पास इतना पैसा कहां से आता था? अब धीरे धीरे उसकी भी परतें खुल रही हैं। अरब देशों से पैसे की व्यवस्था होती थी। लेकिन मामला केवल अरब देशों तक ही सीमित नहीं था। इसके लिए पैसा अमरीका, कनाडा, मलेशिया, तुर्की, पाकिस्तान व कुछ यूरोपीय देशों से भी आता था।

पैसा आने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हवाला तो सर्वविदित है ही। उससे छांगुर ने बेनामी संपत्तियां खरीद रखी थीं। दरअसल सूत्र रूप में कहना हो तो छांगुर ने विदेशी सहायता से भारत के भीतर ही अपना एक छोटा सा राज्य स्थापित कर रखा था। वैसे हम इसे छोटा राज्य कह सकते हैं, लेकिन प्रभाव के लिहाज से इसकी जड़ें देश के लगभग हर हिस्से से जुड़ी हुई थीं। इतना ही नहीं, इसके संबंध भारत में सक्रिय अन्य विविध प्रकार के आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हुए थे। यह भी खबरें आ रही हैं कि छांगुर आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप भी चलाता था। इससे मामला केवल मतांतरण तक सीमित न रह कर देश विरोधी आतंकवादी संगठनों से सांठगांठ का भी बनता है। यह भी चर्चा है कि मलेशिया में रह रहे जाकिर नायक के नेटवर्क का ही एक हिस्सा छांगुर है।

इसमें कोई शक नहीं कि भारत को कमजोर करने या फिर भारत कमजोर ही बना रहे, यह मंशा ताकतवर देशों की रहती ही है। अरब देशों को लगता है कि एटीएम (अरब, तुर्क, मुगल) मूल के देश भारत पर सात-आठ सौ साल राज करने के बाद भी इसे इस्लामी देश नहीं बना सके। उनके मन में यह टीस बनी रहती है। यह टीस एटीएम मूल के उन मुसलमानों के मन में भी रहती है जो एटीएम का राज खत्म हो जाने के बाद भी यहां बस गए थे।

लेकिन उनका मन अभी भी अरब देशों व मध्य एशिया के देशों में बसा रहता है। वे अभी भी हिंदुस्तान को गजवा-ए-हिंद या दारुल इस्लाम बनाने की फिराक में लगे रहते हैं। उस चक्कर में जिन्ना को आगे किया जाता है और कभी भीख मांगने के अड्डे से जमालुद्दीन को उठाकर छांगुर पीर बनाया जाता है। जब एक बार छांगुर का अड्डा जम जाता है तो अलग-अलग देश विरोधी आतंकी संगठन भी उसकी सहायता के लिए जुट जाते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि देश के अनेक हिस्सों में छांगुरों के डेरे पनप रहे हैं।

बिना कानून के डर से। फिर ऐसा समय भी आ जाता है जब कानून ही छांगुर से डरने लगता है। जब कानून ही डरने लगता है तो आम आदमी भी चुप हो जाता है। इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि भिखारी से पीर बनने के षड्यंत्र में किन किन सरकारी-गैर सरकारी लोगों की सक्रिय हिस्सेदारी रही? ये हिस्सेदार ज्यादा खतरनाक हैं। छांगुर का अड्डा उजड़ जाएगा, तो ये कोई और नया छांगुर बना देंगे। इस तरह की देश विरोधी हरकतों पर सख्ती से रोक लगानी होगी, ताकि भारत सुरक्षित रहे।

अंततः छांगुर को नेपाल की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से ही गिरफ्तार किया गया है। छांगुर उस प्रकार का सरगना नहीं था जो बरसों से पुलिस से बच कर भाग रहा हो और राज्य की पुलिस उसके लिए जगह जगह दबिश दे रही हो। इसके विपरीत वह अपने आलीशान महल, जिसे किला भी कहा जा सकता है, में सम्मान सहित रहता था।

कहानी बन जाएंगे एक लाख लोग

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

एशिया के इस सबसे बड़े विस्थापन में चार बड़े कॉलेज, 20 से ज्यादा प्रमुख स्कूल और कई बड़े अस्पताल शामिल हैं। मंदिर और मस्जिद सहित अन्य धर्मस्थल भी टूटेंगे। पांच हजार से ज्यादा छोटे-बड़े दुकानदार भी हटाए जाएंगे। कोई 40 साल पहले तो कोई 60 साल पहले यहां आया था।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली के मोरवा में एक साथ 22 हजार भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। इससे लगभग 30 हजार परिवार जिसमें एक लाख आबादी है, विस्थापित होगी। यह देश की ऊर्जा राजधानी कही जाने वाली सिंगरौली में एशिया का सबसे बड़ा नगरीय विस्थापन होगा। इसके बाद मोरवा शहर कहानी, किस्सों और इतिहास का हिस्सा बन जाएगा।

दरअसल, मोरवा शहर की जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार मिला है। बताया जाता है कि मोरवा में करीब 800 मिलियन टन कोयले का भंडार है। कोल इंडिया की संस्था नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड 927 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर इसमें कोयले का खनन करेगी। मोरवा शहर में बने सभी मकानों, दुकानों, अस्पताल, मंदिर, मस्जिदों को ध्वस्त किया जाएगा। यहां पर रहने वाले लोगों को मुआवजा देकर अन्य जगह पर बसाया जाएगा। प्रशासन इसकी योजना बना चुका है और इस पूरी प्रक्रिया में 30 हजार करोड़ रुपये का व्यय भी होगा।

यहां पर सवाल यह नहीं है कि लोगों को मुआवजा देकर अन्य स्थलों पर शिफट किया जाएगा। लेकिन इस विस्थापन में सबसे बड़ी चुनौती मोरवा खान में एक पूरे शहर को विस्थापित करने से न केवल लोगों को अपनी जमीन और घर छोड़ना पड़ेगा, बल्कि शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है।

एशिया के इस सबसे बड़े विस्थापन में चार बड़े कॉलेज, 20 से ज्यादा प्रमुख स्कूल और कई बड़े अस्पताल शामिल हैं। मंदिर और मस्जिद सहित अन्य धर्मस्थल भी टूटेंगे। पांच हजार से ज्यादा छोटे-बड़े दुकानदार भी हटाए जाएंगे। कोई 40 साल पहले तो कोई 60 साल पहले यहां आया था।

एनसीएल के सर्वे के मुताबिक यहां से करीब 800 मिलियन टन कोयला निकाला जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए भूमि, मकान, दुकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान की नाप शुरू की गई है। इस आधार पर विस्थापितों के पुनर्वास का आकलन करते हुए मुआवजा दिया जाएगा। जिस भूमि का अधिग्रहण

होना है, उस पर एनसीएल का मुख्यालय, आवासीय कालोनी और सिंगरौली नगर निगम के 11 वार्ड और मुख्य बाजार भी हैं। इस विस्थापन के बाद सिंगरौली शहर एक तिहाई ही रह जाएगा। विस्थापन और अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के लिए अभी कोई डेडलाइन तय नहीं है, लेकिन इसे 2032 तक पूरा करने की योजना है।

हालांकि यह सत्य है कि मोरवा के विस्थापितों को मुआवजा दिया जाएगा। यह 35000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। अब देखना होगा कि यह बसे परिवारों को कहां बसाया जाएगा। भारत में इस तरीके से किसी शहर का विस्थापन अनोखा मामला है। हालांकि नर्मदा बचाओ आंदोलन में मुख्य रूप से बांध निर्माण के कारण विस्थापन हुआ था, जिसमें कई गांवों और समुदायों को प्रभावित किया गया था। मुंबई और दिल्ली में भी सफाई योजना के तहत अनियोजित तरीके से विकसित मकानों और झुग्गियों को विस्थापित किया गया, लेकिन मोरवा खान के मामले में, कोयला खनन के कारण एक पूरे शहर को विस्थापित करने की योजना एक अनोखा मामला है जिसमें एक पूरे शहर को एक साथ विस्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

कोयला की चाहत में शहर में विस्थापित करने की चाहत को मैं सरकार की मंशा को गलत तो नहीं कह सकता लेकिन मोरबा शहर को विस्थापित करने के दौरान कई गंभीर चुनौतियां आएंगी। मोरवा की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है। शहर को विस्थापित करने से इस पहचान को खतरा हो सकता है। शहर के निवासी अपनी पारंपरिक प्रथाएं और त्योहारों को मनाते हैं, जो शहर की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। शहर को विस्थापित करने से इन प्रथाओं और त्योहारों को खतरा हो सकता है। शहर के निवासी अपनी स्थानीय भाषा और बोली का उपयोग करते हैं, जो शहर की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विस्थापन से इस भाषा और बोली को खतरा हो सकता है। इसके अलावा शहर के निवासी अपनी स्थानीय कला और शिल्प का उपयोग करते हैं, जो शहर की कलात्मक धरोहर का हिस्सा है।

> मुंबई और दिल्ली में भी सफाई योजना के तहत अनियोजित तरीके से विकसित मकानों और झुग्गियों को विस्थापित किया गया, लेकिन मोरवा खान के मामले में, कोयला खनन के कारण एक पूरे शहर को विस्थापित करने की योजना एक अनोखा मामला है जिसमें एक पूरे शहर को एक साथ विस्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

कला और शिल्प को खतरा हो सकता है। शहर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजन होते हैं, जो शहर की कलात्मक धरोहर का हिस्सा हैं। शहर को विस्थापित करने से इन कार्यक्रमों और आयोजनों को भी खतरा हो सकता है। शहर के विस्थापन से अजीविका और पुनर्वास की समस्याओं के साथ-साथ निवासियों पर मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

मोरवा के लोगों को प्रशासन भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना तो सहज होगा लेकिन उसे इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा ताकि स्थानीय लोगों को सांस्कतिक, कलात्मक और भावनात्मक क्षति कम से कम पहुंचे। लोगों की पहचान, बोली और स्थानीय गौरव को बरकरार रखने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए।

तीर्थस्थलों पर आकस्मिक भगदड़ प्रबंधन की भूमिका पर सुलगते सवाल

अजीत शर्मा

> आंकड़े बताते हैं कि पहले भी भीड़ जुटने के बाद अचानक मचने वाली भगदड़ में कई जानें जा चुकी हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं, अन्य सेलिब्रेटिज के दीदार या यात्रा सम्बन्धी भीड़ बढ़ने के बाद भी महज एक छोटी सी अफवाह कई लोगों की जान ले लेती हैं और बहुतेरे लोगों को घायल कर जाती हैं।

उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित सुप्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में गत रविवार को सुबह आरती के समय अचानक बेकाबू हुई भीड़ से मची भगदड़ से हुए हादसे में जहां 8 लोगों की जान चली गई, वहीं 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे भक्त और भगवान के व्याकुल अन्तर्सम्बन्धों के साथ-साथ मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर भी सुलगते हुए सवाल उठ हैं। ऐसा इसलिए कि अपने आपमें न तो यह पहली घटना है और न ही अंतिम! बावजूद इसके, बेगुनाहों की मौतों का यह सिलसिला कब थमेगा, विश्वास पूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ब्रेक के बाद देश भर के सुप्रसिद्ध मंदिरों या फिर उससे जुड़े अनुष्ठानों में ऐसे हादसे होते रहते हैं।

आंकड़े बताते हैं कि पहले भी भीड़ जुटने के बाद अचानक मचने वाली भगदड़ में कई जानें जा चुकी हैं। सिर्फ मंदिर ही नहीं, अन्य सेलिब्रेटिज के दीदार या यात्रा सम्बन्धी भीड़ बढ़ने के बाद भी महज एक छोटी सी अफवाह कई लोगों की जान ले लेती हैं और बहुतेरे लोगों को घायल कर जाती हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों के शिकार होने की संभावना ज्यादा होती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, गत 4 जून 2025 को आईपीएल में आरसीबी जीत का जश्न मनाने के लिए खेल के मंदिर यानी चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए समारोह में अकस्मात मची भगदड़ से 11 लोग मारे गए।

वहीं, बीते 3 मई 2025 को गोवा के शिरगाओ

गांव में श्री लैराई देवी मंदिर के वार्षिक उत्सव में मची अचानक भगदड़ में छह लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। जबकि गत 15 फरवरी 2025 को रेल यात्रा के मंदिर यानी नई दिल्ली स्टेशन पर अकस्मात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। तब ये लोग महाकुंभ जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वहीं, 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ 'अमृत स्नान' में भाग लेने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुटने के बाद संगम नोज क्षेत्र में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 अन्य घायल हो गए।इससे पहले गत 8 जनवरी 2025 को तिरुमाला हिल्स स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शनम के टिकट के लिए हुई धक्का-मुक्की में छह श्रद्धालु मारे गए, जबकि दर्जनों घायल हो गए।

अब बात करते हैं बीते वर्ष हुई भगदड़ सम्बन्धी घटनाओं की। गत 2 जुलाई 2024 को यूपी के हाथरस में स्वयंभू दलित बाबा समझे जाने वाले भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ से 100 से अधिक मौतें हुई। इससे एक साल पहले यानी 31 मार्च 2023 को इंदौर में एक मंदिर में रामनवमी पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान प्राचीन 'बावड़ी' के ऊपर बनी स्लैब के ढहने से 36 लोगों की मौत हो गई।इससे एक वर्ष पूर्व यानी 1 जनवरी 2022 को जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक घायल हो गए।

इसी प्रकार एक दशक पहले यानी 14 जुलाई 2015 को आंध्रप्रदेश के राजमुंदरी में आयोजित 'पुष्करम' उत्सव के पहले दिन ही गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ मचने से 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। वहीं, 3 अक्टूबर 2014 को दशहरा समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में मची भगदड़ में 32 लोग मारे गए और 26 अन्य घायल हो गए। वहीं, 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए।

यही वजह है कि उपर्युक्त तमाम जगहों के प्रबंधकों/व्यवस्थापकों के साथ-साथ भक्ति या दीवानगी में बेलगाम होते जा रहे श्रद्धालुओं/शुभचिंतकों, अनुगामियों की भूमिका पर सवाल दर सवाल उठ रहे हैं। यह जनपद प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाकामी का भी परिचायक है, क्योंकि देश के विभिन्न जिलों में ऐसी लोमहर्षक और हृदयविदारक घटनाएं ब्रेक के बाद होती रहती हैं, लेकिन हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय नगरीय निकायों/ग्रामीण निकायों के निर्देश पर सक्षम प्रशासन द्वारा या एनडीआरएफ की ओर से ऐसी कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई कि भीड़ बढ़ने के बाद उसपर हर हाल में काबू पाया जा सके। यदि ऐसा संभव होता है कि इन आकस्मिक मौतों और घायलों को होने वाली पीड़ा को टाला जा सकता है।

इसलिए जहां तक मंशा देवी मंदिर पर घटी हालिया भगदड़ का सवाल है तो यह बेहद चिंता की बात है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेशद्वार हरिद्वार को ही माना जाता है। इस अव्यवस्था से पर्यटकों की संख्या भी प्रभावित हो सकती है। यह ठीक है कि हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ में जो बच गए, वे खुद पर माता बड़ी कृपा मान रहे है। लेकिन जिन लोगों की जान इस अप्रत्याशित हादसे में चली गई, आखिर उनकी खता क्या रही होगी, इस पर भगवान भी मौन हैं और श्रद्धालुओं का जत्था स्तब्ध ।ऐसे में प्रारब्ध की बात कहकर आखिर कबतक प्रबंधन सम्बन्धी व प्रशासनिक लापरवाहियों पर खामोश रहा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि हरिद्वार में शिवालिक पहाड़ियों पर लगभग 500 फीट से अधिक ऊंचाई पर मनसा देवी मंदिर स्थित है, जहां की सीढ़ियां भी खड़ी चढ़ाई वाली हैं। दरअसल, कांवड़ यात्रा के कारण बंद हुए रास्ते भी रविवार को खुल गए थे, जिससे मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। सीढ़ियां भी छोटी हैं, जहां बरसात में फिसलन होती है।

इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि मंदिर परिसर में सुबह की आरती के समय भीड़ के बीच अचानक धक्का-मुक्की शुरू हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। यहां भगदड़ से पहले का एक विडियो फुटेज भी सामने आया है। जिससे स्पष्ट होता है कि मंदिर जाने वाला पैदल मार्ग श्रद्धालुओं से खचाखच भरा है। भीड़ इतनी थी कि कि मनसा देवी जाने वाला पैदल मार्ग पर लोग एक-दूसरे से बुरी तरह चिपके हुए थे। इस तरह की स्थिति में तमाम लोग छोटे-छोटे बच्चों के साथ भी भीड़ में फंसे हुए दिख रहे हैं।

बताया जा रहा है कि तभी अचानक किसी ने बिजली का तार टूटने की अफवाह फैला दी और इससे डरकर लोगों में भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे और इस दौरान एक-दूसरे पर गिरने लगे। जो गिर गया, वह फिर उठ नहीं पा रहा था और उसके ऊपर से कितने ही लोग गुजर जा रहे थे। ऐसे में जो बच गए, उनमें से कई घायल है। भगदड़ की सूचना के बाद जब एबुलेंस पहुंची, तो कई घायल लोग प्रवेश द्वार पर लावारिस पड़े हुए थे। देवी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा लाई गई चुनरियां हरिद्वार में पहाड़ी पर स्थित मंदिर की ओर जाने

वाली सीढ़ियों पर बिखरी पड़ी थी। प्रवेश द्वार पर ढेर सारे जूते-चप्पल भी लावारिस पड़े थे।

इस घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया ताकि हताहतों को बचाया जा सके। इसलिए वायरल एक विडियो में एक पुलिसकर्मी घायल बच्चे को गोद में लिए एंबुलेस की ओर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं, एक अन्य एम्बुलेस के अंदर दर्द से तड़प रहा घायल अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ कर रहा था, जो भगदड़ के दौरान बिछड़ गए थे। एक अन्य विडियो में संकरे रास्ते में लोग फंसे हुए नजर आ रहे है, जिसमें बच्चे भी है। भगदड़ से कुछ देर पहले शूट किए गए एक विडियो में एक महिला भीड़ में फंसी हुई दिखाई दे रही है, जो मुश्किल से अपने बच्चे को संभाल पा रही है। विडियो में दिख रही जगह वही है, जहां भगदड़ हुई थी। दर्जनों लोग एक-दूसरे से चिपके हुए थे और मुश्किल से हिल-डुल रहे थे, बस बच्चो को अपने सिर के ऊपर ही उठाए हुए थे। लोगों का कहना है कि प्रशासन भीड़ का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। वहीं, प्रशासन ने कहा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और मंदिर परिसर को खाली करवा लिया गया है। यह घटना सुबह करीब 9 बजे हुई बताई जाती है। वहीं, पुलिस ने कहा है कि श्रद्धालुओं की भीड बढने और अव्यवस्थित एंट्री-एग्जिट की वजह से ये हादसा हुआ। जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त संकरे सीढी मार्ग से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार मंदिर की ओर जा रहे थे।

वहीं, प्रशासन ने दावा किया कि हादसे के बाद मनसा देवी मंदिर परिसर को खाली करवा लिया गया है। इस अप्रत्याशित हादसे के बाद सरकार और प्रशासन दोनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर के पैदल मार्ग पर हुई भगदड़ की घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए है। ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए उन्होंने भी जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों का भी हाल जाना। उन्होंने इस घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की। साथ ही, पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद की बात भी कही।

वहीं, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि, 'हमने तस्वीरों और विडियो की जांच में पाया कि किसी ने बिजली के तार टूटने की अफवाह फैलाई, जबकि घायलों या मृतको को देखकर हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। हम जांच करेंगे कि किसने अफवाह फैलाई। जबकि एसएसपी प्रमेद्र सिंह डोवाल ने बताया कि अफवाह कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है।

उधर, विपक्ष ने भी इस घटना पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरी तरह से प्रशासन की असफलता और सरकार की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास शिवरात्रि के बाद का प्रथम शनिवार और रविवार को हरिद्वार में अधिक भीड़ का समय होता है। यह बात हर वर्ष प्रशासन को मालूम रहती है, फिर श्री प्रशासन ने कोई पुख्ता तैयारी नहीं की। उन्होंने कहा कि सीढ़ी वाले रास्ते को भीड़ बढ़ने पर हमेशा वन-वे कर दिया जाता है, लेकिन रविवार को दोनों और से आवाजाही चालू रखी गई।

वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाबदेही तय किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह केवल हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता है और इसे लेकर जवाबदेही तय की जानी बाहिए। वहीं, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस घटना पर दुख जताया है। वहीं, एक स्थानीय निवासी अजय जायसवाल ने कहा है कि हर की पौड़ी के बाद मनसा देवी हरिद्वार में श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा है। यहां हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं लेकिन सावन में भीड़ बढ़ है। रविवार होने से भीड़ और बढ़ गई। प्रशासन को सतर्क होना था। उधर, प्रभावित लोगों के बारे में जिला आपातकालीन केंद्र, हरिद्वार से 01334-223999, 9068197350. 9528250926 नंबरों पर जानकारी ली जा सकती है, क्योंकि प्रशासन ने इन आपातकालीन नम्बरों को लोगों की सुविधा के लिए जारी किया है।

नहीं रही हैं परेशानी दूर तो मंगलवार के दिन कर लें ये उपाय

हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है। इस दिन संकट मोचन की पूजा की जाती है और कुछ भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि मंगलवार के दिन सच्चे मन से बजरंगबली की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और रुके हुए काम बनने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी कलियुग के सबसे प्रभावशाली देवता है और उनकी भक्ति करने से हर तरह की परेशानियां खत्म हो सकती है। ऐसे में अगर आप अपने जीवन में सुख-शांति चाहते हैं तो मंगलवार के दिन कुछ खास उपाय कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन से उपाय करने चाहिए।

नौकरी में सफलता पाने के लिए करें ये उपाय

अगर आप अपने जीवन में सुख-शांति और सरकार नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही तो मंगलवार के दिन बजरंगबली को पान चढ़ाएं। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और सच्चे दिन से उनकी प्रार्थना करें। मान्यता है कि इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति को नौकरी में सफलता मिलती है।

बिगड़े काम बनाने के लिए

इसके अलावा अगर आपके काम बार-बार बिगड़ रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं और तरक्की के नए अवसर मिलते हैं।

मंगल दोष को दूर करें

वहीं अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है तो यह आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर सकता है। इसे दूर करने के लिए मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को लाल मिर्च दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से मंगल दोष का असर कम हो जाता है और जीवन में खुशहाली आती है।

मनचाही इच्छा होती है पूरी

अगर आप अपनी कोई खास इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहनकर हनुमान जी की पूजा करें। इसके साथ ही उन्हें सिंदूर चढ़ाएं और फिर उसी सिंदूर से अपने माथे पर तिलक लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

रसोई में इन टिप्स को अपनाने से आसान होगा काम, महिलाओं को मिलेगी राहत

किचन में घर की औरतें घंटों मेहनत करती हैं, लेकिन अगर उनके काम को कुछ आसान और उपयोगी किचन टिप्स मिल जाएं। तो न सिर्फ खाना बनना तेज हो सकता है, बल्कि खाना अधिक स्वादिष्ट भी बन सकते हैं।

आज के समय में अगर किसी को थोड़ी सी मदद मिल जाए, तो न सिर्फ काम आसान हो जाता है। बल्कि इससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो जाती है। फिर चाहे ऑफिस का काम हो या घर का। एक-दूसरे की मदद से जिंदगी बेहतर बन सकती है। किचन में घर की औरतें घंटों मेहनत करती हैं, लेकिन अगर उनके काम को कुछ आसान और उपयोगी किचन टिप्स मिल जाएं। तो न सिर्फ खाना बनना तेज हो सकता है, बल्कि खाना अधिक स्वादिष्ट भी बन सकते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ स्मार्ट टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अपनाने से आपका काम आसान बन जाएगा।

आलू उबालने के दौरान डालें नमक और नींबू

अक्सर ऐसा होता है कि उबले हुए आलू का छिलका निकालने में समस्या होती है। ऐसे में आप आलू को उबालने के समय पानी में थोड़ा सा नींबू और नमक डालें। इससे आलू जल्दी गल जाते हैं और इनका स्वाद भी बढ़ जाता है। इससे आलू का छिलका उतारने में भी आसानी होती है।

इडली का बैटर खट्टा होने पर करें ये काम

कई बार ऐसा होता है कि इडली का बैटर खट्टा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका स्वाद बिगड़ जाता है। वहीं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो बैटर में थोड़ा सा नारियल का दूध मिलाएं। इससे बैटर का स्वाद बेहतर हो जाएगा।

दही जमाते समय डालें हरी मिर्च

कई बार दही जमाने के लिए थोड़ा सा भी दही नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दूध में हरी मिर्च डालकर रातभर के लिए फ्रिज में रख दें। आप पाएंगी कि सुबह दही जम चुका होगा और यह जल्दी खराब भी नहीं होता है। वहीं इस तरह से दही अच्छा जमता है।

सब्जी ज्यादा तेल सोखती हो तो ट्राई करें ये तरीका

कई बार सब्जी ज्यादा तेल सोखती है, ऐसे में आप कुछ देर के लिए सब्जी को फ्रिज में रख दें। इससे तेल सब्जी के ऊपर जम जाएगा और सब्जी भी हल्की हो जाएगी। यह नुस्खा ट्राई करने के बाद भी सब्जी का स्वाद बरकरार रहेगा।

डस्की स्किन वाली महिलाओं जरूर ट्राई करें ये मेकअप हैक्स, बढ़ जाएगी चेहरे की खूबसूरती

आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ब्यूटी एक्सपर्ट की मदद से कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। जिनका इस्तेमाल करने से आप आसानी से डस्की स्किन को खूबसूरत बना सकती हैं। हम आपको डस्की स्किन पर मेकअप करने के लिए आप कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं।

हर महिला खूबसूरत दिखना चाहती हैं, जिसके लिए वह काफी प्रयास भी करती हैं। डस्की स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए महिलाएं महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर आपकी स्किन भी डस्की है, तो आप भी अपने चेहरे को खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए मेकअप करती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ब्यूटी एक्सपर्ट की मदद से कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। जिनका इस्तेमाल करने से आप आसानी से डस्की स्किन को खूबसूरत बना सकती हैं। हम आपको डस्की स्किन पर मेकअप करने के लिए आप कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं।

सही फाउंडेशन

मेकअप करने से पहले सही फाउंडेशन का चुनाव करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में आप ऑरेंज या ब्राउन टोन फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह डस्की स्किन के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है।

कोरल शेड ब्लश

डस्की स्किन वाली लड़कियां कोरल शेड ब्लश का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह इस स्किन टोन वाली लड़कियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं आंखों का मेकअप करने के लिए आप ब्लैक कलर के लाइनर का यूज कर सकती हैं। वहीं आप आईशैडो भी लाइट कलर को चुनें।

वॉर्म टोन लिपस्टिक

अगर आप लिपस्टिक के कलर को चुनने में कंफ्यूज हो रही हैं, तो डस्की स्किन वाली लड़कियां वॉर्म टोन वाली लिपस्टिक चुन सकती हैं। यह शेड्स आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में सहायता करते हैं।

न्यूड शेड कंपैक्ट पाउडर

मेकअप के समय जब भी आप कंपैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करें, तो इसका शेड न्यूड ही रखें। यह कंपैक्ट पाउडर मेकअप को खास बनाने में मदद करेगा। डस्की स्किन वाली लड़कियों के लिए यह मेकअप टिप्स बहुत काम आएंगे।

केरल की इन हसीन जगहों को करें एक्सप्लोर पार्टनर के साथ बिता सकेंगे रोमांटिक पल

जब भी दक्षिण भारतीय राज्यों में घूमने की बात होती है, तो लोग सबसे पहले केरल का नाम लेते हैं। अरब सागर के तट पर स्थित केरल एक बेहद खूबसूरत राज्य है। जहां पर हर दिन हजारों पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं।

केरल में कपल्स को हिल स्टेशन्स से लेकर समुद्री इलाके सबसे आकर्षिक करते हैं। इसलिए हर महीने दर्जन से भी अधिक कपल्स केरल रोमांटिक वेकेशन पर जाते हैं। अगस्त साल का एक ऐसा महीना है, जब कपल्स केरल में छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको केरल की कुछ रोमांटिक डेस्टिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर आप भी अपने पार्टनर के साथ हसीन पल बिताने के लिए पहुंच सकते हैं।

अल्लेप्पी

अगस्त के महीने में केरल की सबसे खूबसूरत और रोमांटिक जगह घूमने की बात की जाती है, तो कई कपल्स सबसे पहले अल्लेप्पी पहुंचते हैं। यह जगह अपनी खूबसूरती और मेहमान नवाजी के कारण केरल के टॉप हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। यह जगह अपने सबसे सुंदर बैकवाटर, लैगून और खूबसूरत बीचेज के लिए जाना जाता है। यहां पर समुद्र तट के किनारे कई ऐसे रिसॉर्ट और विला हैं, जो कपल्स का शानदार वेलकम करते हैं। वहीं आप खूबसूरत बीच के किनारे खुशनुमा सुबह से लेकर हसीन शाम का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं पार्टनर के साथ हाउसबोट्स का भी आनंद ले सकते हैं।

वायनाड

वैसे केरल का मुन्नार तो हर कोई घूमने जाता है, लेकिन अगर आप किसी भीड़-भाड़ से दूर शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आपको वायनाड को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। यहां पर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक और क्वांटिटी टाइम बिता सकेंगे। वायनाड एक बेहद शानदार और खूबसूरत हिल

स्टेशन है। जोकि अपने चाय-काफी के बागान, हरियाली और शानदार वॉटरफॉल के लिए फेमस है। यहां पर कई ऐसे रिसॉर्ट और विला हैं, जहां पर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिता सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर कुरुवा द्वीप, चेम्बरा पीक और बाणासुर सागर बांध जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

कोवलम

केरल के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में कोवलम का नाम भी शामिल है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है। यहां पर सिर्फ अगस्त के महीने में नहीं बल्कि हर महीने पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। यह जगह अपने अधिक समुद्र तटों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहां पर हवा बीच, लाइट हाउस बीच और कोवलम बीच के किनारे कई कपल्स हनीमून के लिए भी पहुंचते हैं।

त्रिशूर

केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फेमस त्रिशूर घूमने के लिहाज से एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यह केरल का ऐतिहासिक और धार्मिक शहर माना जाता है। त्रिशूर में आपको खूबसूरती से लेकर स्थानीय संस्कृति का बेजोड़ नमूना देखने का मौका मिलेगा। आप यहां पर अथिरापल्ली झरना, वड़ाकुमनाथन मंदिर आदि को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।

लाइलाज बीमारी डीएमडी से जूझते बच्चे

डीएमडी के बारे में भारत में जागरूकता का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। बहुत कम लोग इस बीमारी को समझते हैं, जिसके कारण मरीजों और उनके परिवारों को सामाजिक समर्थन नहीं मिल पाता।

ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (DMD) एक ऐसी दुर्लभ और लाइलाज जेनेटिक बीमारी है, जो मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करती है। यह बीमारी मांसपेशियों को धीरे-धीरे कमजोर करती है, जिससे रोगी का चलना-फिरना, सांस लेना और अंततः जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। भारत में हर 3500 पुरुष जन्मों में से एक बच्चा इस बीमारी का शिकार होता है। इसका इलाज इतना महंगा है कि यह सामान्य परिवारों की पहुंच से बाहर है। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी है अमृतसर के जंडियाला गुरु निवासी हरप्रीत सिंह और उनकी पत्नी की, जो अपने 9 वर्षीय बेटे

डॉ. मुकुल शर्मा

इशमीत को बचाने के लिए दिन-रात संघर्ष कर रहे हैं। इशमीत को डीएमडी है और उसके इलाज के लिए 27 करोड़ रुपये की जरूरत है, एक ऐसी राशि जो किसी सामान्य परिवार के लिए असंभव-सी प्रतीत होती है।

हरप्रीत सिंह भारतीय सेना में सैनिक हैं और उनकी पत्नी का जीवन तब तक सामान्य था, जब तक उनके इकलौते बेटे इशमीत में कुछ असामान्य लक्षण दिखाई नहीं दिए। इशमीत जब चार साल का था तब उसके माता-पिता ने देखा कि वह ठीक से चल नहीं पाता, बार-बार गिरता है और अन्य बच्चों की तरह दौड़-भाग नहीं कर पाता। शुरू में उन्होंने इसे सामान्य कमजोरी समझा, लेकिन जब लक्षण बढ़ने लगे, तो वे उसे स्थानीय डॉक्टरों के पास ले गए। कई जांचों और अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद, दिल्ली के एम्स में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि इशमीत डीएमडी से पीड़ित है। यह खबर सुनकर हरप्रीत और उनकी पत्नी के पैरों तले जमीन

बीमारी को लेकर जागरूकता का अभाव

डीएमडी के बारे में भारत में जागरूकता का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। बहुत कम लोग इस बीमारी को समझते हैं, जिसके कारण मरीजों और उनके परिवारों को सामाजिक समर्थन नहीं मिल पाता। 2023 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर डीएमडी जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई थी जिसमें 21 राज्यों से करीब 500 परिवार शामिल हुए। इस रैली में माता-पिता ने सरकार से सस्ती दवाओं, शोध के लिए फंड और मुफ्त इलाज की मांग की थी। हरप्रीत जैसे परिवारों का मानना है कि अगर समाज इस बीमारी को समझे और सरकार इसमें शोध को प्रोत्साहित करे, तो शायद भविष्य में इलाज किफायती हो सके। हरप्रीत और उनकी पत्नी का संघर्ष केवल इशमीत के लिए नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए एक मिसाल है, जो डीएमडी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनकी कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या भारत जैसे देश में, जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही चुनौतियों से भरी हैं, दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को जीने का हक मिलेगा? क्या समाज और सरकार मिलकर इन परिवारों के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं? यह न केवल हृदयविदारक है, बल्कि यह समाज और सरकार के लिए एक आंख खोलने वाली सीख भी है। 27 करोड़ रुपये का इलाज एक असंभव लक्ष्य जरूर है, लेकिन अगर समाज एकजुट हो जाए और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए, तो इशमीत जैसे बच्चों को नया जीवन मिल सकता है। डीएमडी से जूझ रहे बच्चों के लिए जागरूकता, शोध और किफायती इलाज की जरूरत है।

डीएमडी ऊपर सरकार की कोई ठोस नीति नहीं

डीएमडी जैसी दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए भारत में कोई ठोस नीति या सरकारी सहायता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में बताया था कि देश में करीब पांच लाख लोग डीएमडी से पीड़ित हैं और प्रत्येक मरीज के इलाज पर सालाना पांच करोड़ रुपये का खर्च आता है। लेकिन बजट की कमी के कारण सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा पा रही। हरप्रीत ने कई बार सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले। डीएमडी के मरीजों के लिए न तो मुफ्त दवाएं उपलब्ध हैं, न ही फिजियोथेरेपी जैसी सहायक सेवाएं। ऐसे में परिवार अकेले ही इस जंग को लड़ने के लिए मजबूर हैं।

खिसक गई। डीएमडी एक अनुवांशिक बीमारी है, जो डिस्ट्रोफिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होती है। यह जीन शरीर में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का निर्माण करता है, जो मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए जरूरी होता है। इस प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमजोर होकर धीरे-धीरे नष्ट हो जाती हैं। डीएमडी से पीड़ित बच्चों की औसत आयु 11 से 21 वर्ष तक होती है और ज्यादातर मरीज किशोरावस्था के अंत तक व्हीलचेयर पर निर्भर हो जाते हैं।

जब हरप्रीत को पता चला कि उनके बेटे का इलाज संभव है तो उनके चेहरे पर उम्मीद की किरण जगी। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि अमेरिका में एक जीन थेरेपी उपलब्ध है, जिसमें एक विशेष इंजेक्शन जोल्जेंस्मा (या समकक्ष दवा) के जरिए डीएमडी का इलाज किया जा सकता है। डॉक्टरों ने आश्वासन दिया कि यह इंजेक्शन इशमीत को पूरी तरह स्वस्थ कर सकता है। लेकिन इस उम्मीद के साथ एक ऐसी सच्चाई भी सामने आई जिसने परिवार को हताश कर दिया। इस इंजेक्शन की कीमत 27 करोड़ रुपये है।

27 करोड़ रुपये की यह राशि किसी मध्यमवर्गीय परिवार के लिए कल्पनातीत है। हरप्रीत सिंह ने अपनी सारी जमा-पूंजी, जमीन, और अन्य संसाधनों को बेचने की कोशिश की, लेकिन इससे भी इस राशि का एक छोटा सा हिस्सा ही जुट पाया। भारत में डीएमडी का कोई किफायती इलाज उपलब्ध नहीं है और स्टेरॉयड जैसी दवाएं केवल लक्षणों को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर सकती हैं, जिनके गंभीर दुष्प्रभाव भी हैं।

हरप्रीत और उनकी पत्नी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लिया। सोशल मीडिया, स्थानीय समुदाय और विभिन्न संगठनों के माध्यम से उन्होंने लोगों से मदद की अपील की। श्री हरिमंदिर साहिब के बाहर खड़े होकर उन्होंने गुहार लगाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी कहानी सुन सकें। उनकी मेहनत रंग लाई और अब तक करीब दो करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। लेकिन अभी भी पच्चीस करोड़ रुपये की जरूरत है और समय तेजी से बीत रहा है।

पहली ही फिल्म फ्लॉप

फिर चल पड़ी काजोल के कैरियर की गाड़ी

आकांशा गर्ग

बॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री काजोल 51 वर्ष की हो गईं। पांच, 1974 को मुंबई में जन्मी काजोल को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता सोमु मुखर्जी निर्माता, जबकि मां तनुजा जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थीं। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण काजोल अकसर अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। इस वजह से उनका भी रूझान फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेत्री बनने के ख्वाब देखने लगी। काजोल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संत जोसेफ कान्वेंट पंचगनी से की। इसके बाद उन्होंने बतौर अभिनेत्री अपने सिने करियर की शुरूआत वर्ष 1992 में प्रदर्शित फिल्म 'बेखुदी' से की। युवा प्रेम कथा पर बनी इस फिल्म में उनके नायक की भूमिका कमल सदाना ने निभाई, लेकिन कमजोर पटकथा और निर्देशन के कारण फिल्म टिकट खिड़की पर असफल साबित हुई।

वर्ष 1993 में काजोल को अब्बास-मुस्तान की फिल्म 'बाजीगर' में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनके नायक की भूमिका शाहरूख खान ने निभाई थी। यूं तो पूरी फिल्म शाहरूख खान पर केंद्रित करके बनाई गई है, लेकिन काजोल ने अपने दमदार अभिनय से दर्शको का दिल जीत लिया। वर्ष 1994 काजोल के सिने कैरियर में अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी उधार की जिंदगी, ये दिल्लगी और करण अर्जुन जैसी फिल्म प्रदर्शित हुई। उधार की जिंदगी टिकट खिडकी पर असफल साबित हुई, लेकिन काजोल ने अपने दमदार अभिनय से दर्शको का दिल जीत लिया, वहीं बांबे फिल्म जर्नलिस्ट ऐशोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित की गई। वर्ष 1994 में

ही काजोल को यश चोपड़ा के बैनर तले बनी फिल्म ये दिल्लगी में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनके नायक की भूमिका अक्षय कुमार और सैफ अली खान ने निभाई। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए वह पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की गयी। वर्ष 1995 में काजोल को यश चोपड़ा की ही फिल्म ..दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे.. में काम करने का अवसर मिला जो उनके सिने कैरियर के लिये मील का पत्थर साबित हुई। काजोल और शाहरूख खान के बेहतरीन अभिनय से सजी यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई।

वर्ष 1997 में काजोल को निमार्ता निर्देशक राजीव राय की फिल्म 'गुप्त' में काम करने का अवसर मिला। वह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। फिल्म गुप्त ..में काजोल का किरदार ग्रे शेडस लिये हुये था। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिये वह सर्वश्रेष्ठ खलनायक के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की गयी। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास का पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था ।वर्ष 1998 में काजोल के सिने करियर की एक और अहम फिल्म 'दुश्मन' प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में काजोल ने अपने सिने करियर में पहली बार दोहरी भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की गईं। वर्ष 1998 में ही काजोल की प्यार तो होना ही था और कुछ-कुछ होता है जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं। इन दोनों फिल्मों के लिए भी वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई। यह उनके सिने करियर में पहला अवसर था जब एक वर्ष में तीन फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वर्ष 1999 में काजोल को सतीश कौशिक निर्देशित फिल्म 'हम आपके दिल में रहते है' में काम करने का मौका मिला।

फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए काजोल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिये नामांकित भी की गई। इसी वर्ष काजोल ने अभिनेता अजय देवगन के साथ शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना काफी हद तक कम कर दिया। वर्ष 2001 में प्रदर्शित फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के बाद काजोल ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। वर्ष 2006 में काजोल ने यश चोपड़ा के बैनर तले बनी फिल्म 'फना' के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धमाकेदार वापसी की। काजोल के सिने कैरियर में उनकी जोड़ी अभिनेता शाहरूख खान के साथ खूब जमी। काजोल अपने सिने कैरियर में चार बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है। वर्ष 2011 में काजोल पदमश्री पुरस्कार से भी सम्मानित की गईं। काजोल ने वर्ष 2015 में प्रदर्शित फिल्म दिलवाले से कमबैक किया। रोहित धवन के निर्देशन में बनी फिल्म दिलवाले में शाहरूख के साथ काजोल की केमेस्ट्री को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिल्म दिलवाले टिकट खिडकी पर हिट साबित हुई। वर्ष 2018 में काजोल की फिल्म हेलीकॉप्टर इला प्रदर्शित हुई, लेकिन कोई कमाल नहीं दिखा सकी। वर्ष 2020 में काजोल ने अजय देवगन के साथ की फिल्म तानाजीः दि अनसंग हीरो में काम किया जो सुपरहिट साबित हुई। काजोल की हाल ही में फिल्म मां प्रदर्शित हुई है।

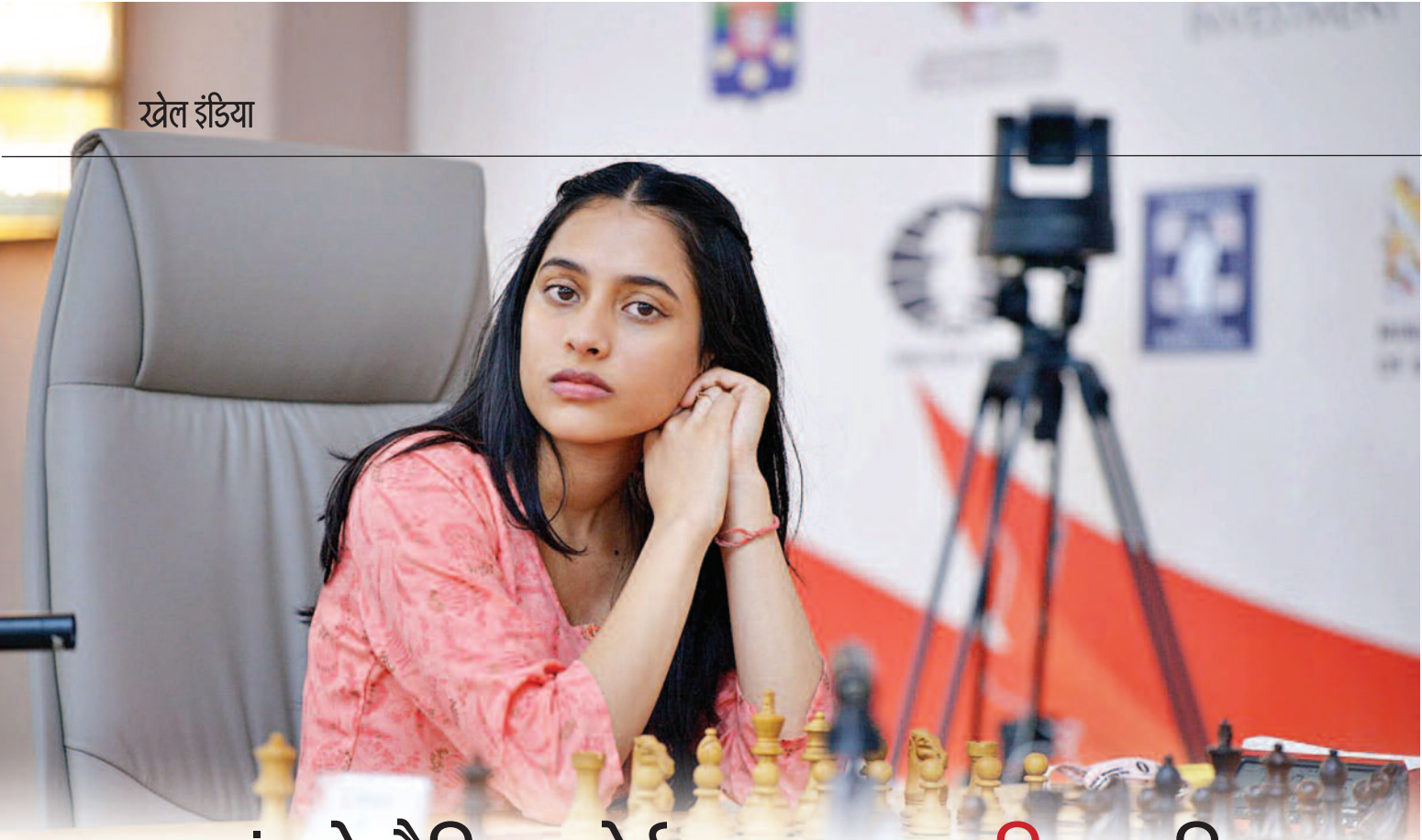

शतरंज के वैश्विक बोर्ड पर भारत का दिव्य अधिकार

नागपुर की रहने वाली 19 वर्षीया दिव्या देशमुख भविष्य में कई युवाओं को उसी प्रकार से खेल के प्रति उत्साहित करने में सक्षम हो गई हैं जैसे कि भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। दिव्या के पिता डा. जितेंद्र और माता नम्रता देशमुख दोनों ही चिकित्सक हैं।

वैश्विक शतरंज में वर्ष 2025 एक ऐसी दिव्य उपलब्धि लेकर आया है जिसे तब तक स्मरण किया जाएगा जब तक वैश्विक मंच पर शतरंज खेला जाएगा और शतरंज के प्रेमी रहेंगे। भारत की 88वीं ग्रेंड मास्टर बनीं 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने जार्जिया के बाटुमी में हुए फिडे महिला शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता में अपने ही देश की कोनेरू हंपी को पराजित करते हुए इतिहास रच दिया। इसके साथ ही दिव्या शतरंज के खेल की नई सनसनी बन गई हैं। अभी तक दिव्या को 15वी वरीयता प्राप्त थी किंतु दृढ़ता और ओपनिग की तैयारियों ने दिव्या को चैपिंयन बना दिया है।

नागपुर की रहने वाली 19 वर्षीया दिव्या देशमुख भविष्य में कई युवाओं को उसी प्रकार से खेल के प्रति उत्साहित करने में सक्षम हो गई हैं जैसे कि भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। दिव्या के पिता डा. जितेंद्र और माता नम्रता देशमुख दोनों ही चिकित्सक हैं। दिव्या ने सबसे पहले 2012 में अंडर-सात में राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। दिव्या ने 214 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में अंडर 10 और 2017 में ब्राजील में अंडर -12 वर्ल्ड यूथ खिताब जीते। वह 2021 में विदर्भ क्षेत्र की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनीं। उन्होंने 2023 में इंटरनेशनल मास्टर की प्रतियोगिता जीती। फिर उन्होंने ग्रैड मास्टर आर. बी. रमेश के मार्गदर्शन में चेन्नई के शतरंज गुरूकुल में अपनि प्रतिभा का परिचय दिया।

दिव्या शतरंज ओलम्पियाड में तीन बार की स्वर्ण पदक विजेता हैं। दिव्या ने एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में भी स्वर्णपदक जीता। दिव्या ने वर्ष 2024 में बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलम्पियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और वर्ल्ड टीम रैपिड और बिल्ट्ज शतरंज प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन किया।

दिव्या की बड़ी बहन बैइमिंटन खेलने के लिए जाती थीं और उनके साथ दिव्या भी जाती थी किंतु उन्हें शतरंज में रूचि थी और वे उसी में रम गईं आज वह शतरंज की सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। वर्ष 2025 में दिव्या ने चीन की 22 वर्षीय ग्रैंडमास्टर झू जिनर को हराकर शानदार जीत हासिल की, वहीं दूसरी भारतीय महिला खिलाडी कोनेरू हंपी ने भी चीनी खिलाड़ी को ही हराकर फिडे शतरंज विश्वकप में चीन का दबदबा ध्वस्त कर दिया है। यह भारत के लिए बड़ी अभूतपूर्व दोहरी सफलता रही है कि फिडे विश्व कप के फाइनल में दोनों ही खिलाड़ी भारतीय रहे ।

अब विश्व शतरंज में भारत की धमक बढ़ रही है और भारत के खिलाड़ी देश का ध्वज शतरंज के बोर्ड पर लहरा रहे हैं। इससे पूर्व पुरुष शतरांज में 18 वर्षीय डी. गुकेश ने चीन के डिग लिरेन को हराकर कीर्तिमान रचा था। उनकी यह उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि ही नहीं थी अपितु भारतीय शतरांज की एक बड़ी छलांग थी। विगत वर्ष सितंबर माह में ही भारत ने बुडापेस्ट में हुए 45वें शतरंज ओलम्पियाड में भी शानदार प्रदर्शन किया थ जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश को गर्व से भर दिया था। भारत के कई अन्य ग्रैंड मास्टर भी वैश्विक जगत में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। जिसमें आर. प्रगनानंद, विदित गुजराती, अर्जुन ऐरिगिसी, आर वैशाली और डी. हरिका जैसे युवा खिलाड़ी प्रमुख हैं।

आज पूरा भारत शतरंज की दुनिया में अपनी बेटियो की सफलता पर गर्व का अनुभव कर रहा है। भविष्य में यही युवा खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्वर बनने जा रहे हैं। अब शतरंज के आकाश पर भारत का राज स्थपित हो रहा है। यह पल भारत के लिए बेहद गर्व के पल हैं।

क्रिकेट खेलने की विवशता

टी-20 क्रिकेट का 'एशिया कप' संयुक्त अरब अमीरात के शहरों में खेला जाएगा। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इस टूर्नामेंट का मेजबान है, लेकिन मुकाबले 'तटस्थ जगह' पर खेलना तय हुआ है। टूर्नामेंट 9-28 सितंबर के बीच खेला जाएगा, जिसके दौरान 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान का विस्फोटक मैच खेला जाएगा। 'सुपर फोर' के मुकाबले में भी 21 सितंबर को दोबारा दोनों देशों की टीमें भिड़ सकती हैं।

यदि भारत-पाक की टीमें, अंततः,फाइनल में पहुंचने में सफल रहीं, तो एक बार फिर तनावपूर्ण मुकाबला होगा। आश्चर्य और सवालिया है कि भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की इजाजत बीसीसीआई को क्यों दी? एक तरफ खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 'राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक' लोकसभा में पेश किया है। उसके जरिए भारत सरकार सभी खेल संघों और महासंघों के गले में घंटी बांधना चाहती है। उनकी स्वायत्तता पर अंकुश लगाना चाहती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट के निर्णय का उल्लंघन यह 'एशिया कप' है। जब तय कर लिया कि पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ-साथ कोई व्यापार, जल, संवाद नहीं किया जाएगा, तो क्रिकेट खेलने की विवशता क्या है? क्या 22 अप्रैल का 'पहलगाम नरसंहार' भुला दिया गया?

'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत हमारी सेनाओं को पाकिस्तान के साथ जो युद्ध-सा संघर्ष लड़ना पड़ा, क्या बीसीसीआई और भारत सरकार के लिए उसका कोई महत्व नहीं है? क्या बेगुनाह लोगों की शहादत और राष्ट्र से अधिक महत्वपूर्ण पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना है? जब पाकिस्तान का चौतरफा बहिष्कार जारी है, तो क्रिकेट के जरिए कौनसे संबंध जिंदा रह सकते हैं? यह शर्मनाक, देश-विरोधी, सेना-विरोधी निर्णय है।

क्या बीसीसीआई इतना निरंकुश और खुदमुख्तार हो गया है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और एशिया क्रिकेट परिषद की करीब 90 फीसदी फंडिंग बीसीसीआई करता है। आईसीसी का अध्यक्ष जय शाह हैं, जो गृहमंत्री अमित शाह के सुपुत्र हैं। क्रिकेट में उनका अमूल्य योगदान क्या रहा है, जो

इस पद पर विराजमान किया गया? यदि भारत पाकिस्तान के साथ खेलने से इंकार करता है, तो कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है? भारत की अपनी सटीक दलीलें हैं।

बीसीसीआई के 30,000 करोड़ रुपए बैंकों में सुरक्षित जमा हैं, जिस पर 1000 करोड़ रुपए का सालाना ब्याज मिलता है। आईपीएल टूर्नामेंट से भी बोर्ड को 5000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई हुई है। चूंकि भारत सरकार क्रिकेट बोर्ड को एक रुपया भी अनुदान नहीं देती है, वह किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह अमीर और संपन्न है, लिहाजा वह अपनी मर्जी का मालिक है। कुछ साल पहले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने क्रिकेट के क्रिया-कलापों में सुधार के मद्देनजर जस्टिस आरएम लोढा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। क्रिकेट बोर्ड पर लगाम लगाने की कोशिश की गई थी।

बीसीसीआई किसी भी तरह के सरकारी कायदे-कानूनों का विरोध करता रहा है। अन्य खेल संघों के विपरीत क्रिकेट बोर्ड सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं है। चूंकि अब 2028 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया है, लिहाजा सरकार प्रस्तावित बिल के जरिए बीसीसीआई को भी, अन्य खेल संघों की तरह, अपने नियमनों की परिधि में आने को विवश कर सकती है। पेश किए गए बिल में राष्ट्रीय खेल बोर्ड को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। यदि यह बिल संसद में पारित होकर कानून बन जाता है, तो बीसीसीआई के गले में भी घंटी बंध जाएगी। दरअसल भारत सरकार इस विधेयक के जरिए खेल संघों, परिषदों और महासंघों के भीतर का भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, कानूनी विवाद, निहित स्वार्थ आदि को बिल्कुल साफ कर देना चाहती है। यदि यह कानून बना, तो दो मुख्य स्तंभों पर राष्ट्रीय खेल बोर्ड टिका होगा। यह सेबी की तरह काम करेगा। बहरहाल बीसीसीआई जैसे संघों की निरंकुशता जरूर टूटनी चाहिए।

WI
welcome
INDIA
PACKAGED DRINKING WATER

NABCB
QMS 008
AN ISO 9001 -2000 COMPANY

IS:8931

CM/L-3228449

supreme
luxury bathing

Assuring Excellence in Bath Faucets

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

यूपी बन रहा टेक्नो-हब

- 6 विभागों में AI कौशल उन्नयन, 10 लाख लोग होंगे प्रशिक्षित
- महाकुम्भ-2025 की अभेद्य सुरक्षा में AI का व्यापक उपयोग
- इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग में 4 लाख+ रोजगार के अवसर

- जेवर में ₹3,700 करोड़ की सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी
- उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू
- यूपी की GDP में IT सेक्टर का 3.2 प्रतिशत योगदान
- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी निर्यात में तीव्र वृद्धि
- नोएडा, लखनऊ एवं कानपुर में टेक्नोलॉजी हब
- AI, क्लाउड कंप्यूटिंग एवं साइबर सिक्योरिटी का उन्नयन
- देश के 45% स्मार्टफोन एवं 55% मोबाइल पार्ट्स का निर्माण यूपी में

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

6 शहरों में स्थापित

3 शहरों में निर्माणाधीन

काम दमदार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP